वर्ष-1, अंक-04, मार्च-2026

R.N.I.No.UPHIN/25/A3973

मूल्य-10/- रूपए

हिन्दी मासिक पत्रिका

खुशी समय

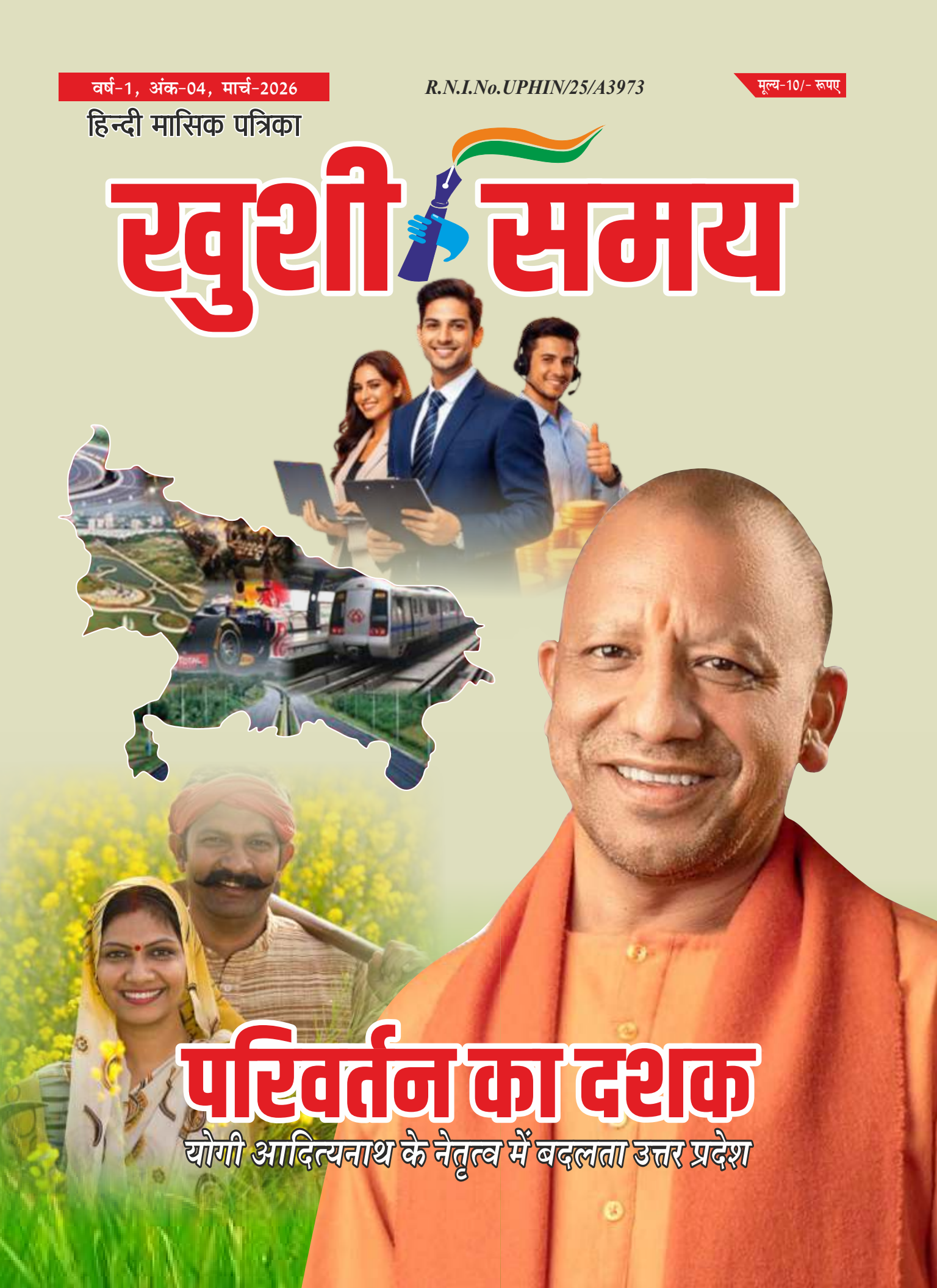

परिवर्तन का दशक

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बदलता उत्तर प्रदेश

Complete Health Care Under One Roof

Dr. Dwivedi's
KHUSHI MEDICAL & RESEARCH CENTER

(A Multi-Speciality Medical-Health Center)

SHOP-15/107, 15/25, Ganesh Market, , Near C-Block Chauraha,
Opposite Hanuman Mandir, Indira Nagar, Lucknow-226016

Phone : 9450097512 * 8090111100

E-mail: kmrc.india@gmail.com

PATHOLOGY

Dr Lal PathLabs

HOMEOPATHY

Khushi Homeopathic Clinic & Research Center
Lucknow's Best Homeopathic Research Center for Chronic Diseases

PHYSIOTHERAPY

Khushi Physiotheraphy Clinic & Research Center
Finest Physiotherapy Clinic with Modern Machines and Complete Rehabilitation

Homeopathic Consultation • Pathology • Physiotherapy
Homeopathic Pharmacy • Diagnostics • Health Check-ups

R.N.I.No.UPHIN/25/A3973

खुशी समय

हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:01 अंक:04 मार्च-2026

संरक्षक

एस.पी. द्विवेदी

सलाहकार

अरविन्द पाण्डेय

शशिधर द्विवेदी

कार्यकारी सम्पादक

एस. एन. लाल

संपादक

अम्ब्रीश द्विवेदी

कानूनी सलाहकार

अजय श्रीवास्तव, एडवोकेट

ब्यूरो चीफ

प्रभात पाण्डेय

संवाददाता

बसन्त कुमार सिंह	- बलिया
ऋचा	- बाराबंकी
रवि प्रताप सिंह	- गोरखपुर
संतोष गुप्ता	- दिल्ली
गौरव शुक्ला	- गोण्डा
रमेश कुमार	- प्रयागराज

स्वामी, प्रकाशक व सम्पादक अम्ब्रीश द्विवेदी ने मुद्रक सुरेश कश्यप, प्लाट संख्या-38, गाटा संख्या 99, ग्राम कपासी, लखनऊ उ.प्र. से मुद्रित करवा कर सी-695, निकट अरावली मार्ग, सेकटर-6, इन्दिरानगर, लखनऊ उ.प्र. से प्रकाशित किया।

मो0: 8090111100

सम्पादक अम्ब्रीश द्विवेदी

पत्रिका के सभी पद अवैतनिक है। प्रकाशित लेख, समाचार, विचार व आंकड़े रचनाकारों के हैं। उन विचारों से सहमत होना संपादक के लिए आवश्यक नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय स्थल लखनऊ होगा।

इस अंक में

08 **परिवर्तन का दशक**

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बदलता उत्तर प्रदेश

12 **चुनावी लोक-लुभावने वादों से दूर, योजनाओं को पूरा करने पर जोर**

06 **अमेरिकी जनता नहीं चाहती है ईरान युद्ध**

31 **पुरुष और महिला खिलाड़ियों के सालाना प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा**

यूपी को आगे बढ़ाने वाला बजट

उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि यह राज्य की विकास दृष्टि और प्राथमिकताओं का व्यापक दस्तावेज भी होता है। फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट इसी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए पेश किया गया यह बजट 9,12,696 करोड़ रुपये का है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है।यह बजट केवल आकार में बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी संरचना और प्राथमिकताओं में भी व्यापक बदलाव दिखाई देता है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों को राहत, शिक्षा और स्वास्थ्य के विस्तार तथा बुनियादी ढांचे के बड़े निवेश को इसमें केंद्र में रखा गया है। इसके साथ ही "टेक युवा" और "समर्थ युवा" जैसी नई योजनाओं के जरिए सरकार ने राज्य की युवा आबादी को तकनीक और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की है।उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है—राज्य को आने वाले समय में *एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था* बनाना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल आर्थिक विकास दर बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजगार, मानव संसाधन, कृषि उत्पादकता और औद्योगिक निवेश को भी समान रूप से बढ़ाना होगा।फरवरी में पेश किया गया बजट इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इसमें लगभग 43,000 करोड़ से अधिक की नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं।सरकार का दावा है कि यह बजट विकास और कल्याण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है—जहां एक ओर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य माना जाता है। यहां हर वर्ष लाखों छात्र उच्च शिक्षा पूरी करके रोजगार के बाजार में प्रवेश करते हैं। ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है।इस बजट में युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इसमें सरकारी भर्तियों के साथ-साथ निजी निवेश और स्वरोजगार के अवसरों को भी शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि यदि उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए तो रोजगार के नए अवसर स्वतः पैदा होंगे। इसी सोच के तहत "टेक युवा योजना" शुरू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक और डिजिटल कौशल से जोड़ना है। इस बजट में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को भी विशेष महत्व दिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि यदि महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करती हैं तो प्रदेश की विकास दर को नई गति मिल सकती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजनाओं को बजट में और विस्तार दिया गया है। इन समूहों के जरिए महिलाएं कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

तेहरान पर हमले का मकसद 'सरकार गिराना'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इजरायल के साथ मिलकर की गई कार्रवाई का मकसद वर्तमान सरकार को गिराना और आम ईरानियों को सत्ता पर काबिज होने की छूट देना बताया। ट्रंप ने हमलों की पुष्टि करते हुए आठ मिनट का वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा, "इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों, सैन्य बलों और सभी पुलिस कर्मियों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने हथियार डाल दें और खुद को बचा लें, वरना आपकी मौत तय है।"

ट्रंप का दावा-ईरान में सैन्य ऑपरेशन अभी चलेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है।" ट्रंप के मुताबिक, अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ट्रंप ने आगे कहा कि जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के विकल्प पर विचार नहीं किया। उन्होंने "हमारी ओर से सुझाए मौके को तरजीह नहीं दी, इसलिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने कहा है कि ईरान में चल रही सैन्य कार्रवाई के दौरान कुछ अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। उन्होंने कहा कि युद्ध में ये नुकसान हो सकता है, लेकिन यह कदम भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है।

यूएस के राष्ट्रपति ने ईरानी जनता से कहा, "ईरान के महान लोगों से, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी आजादी का समय आ गया है। सुरक्षित रहें। अपने घर से बाहर न निकलें। बाहर बहुत खतरा है। हर जगह बम गिर रहे होंगे।" फिर सलाह दी, "जब हमारा काम हो जाएगा, तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लीजिएगा। यह आपकी होगी। यह शायद पीढ़ियों के लिए आपका एकमात्र मौका होगा।" ट्रंप ने अपनी बात को विराम देते हुए कहा, "कई सालों से, आपने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन आपको कभी नहीं मिली... तो देखते हैं आप कैसे जवाब देते हैं। अमेरिका बहुत पूरी ताकत के साथ आपका साथ दे रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी किस्मत पर कंट्रोल करें और अपने पास मौजूद खुशहाल और शानदार भविष्य को सामने लाएं। यह एक्शन लेने का समय है। इसे जाने न दें।"

अमेरिकी जनता नहीं चाहती है ईरान युद्ध

ईरान युद्ध के मसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प अपने ही मुल्क में घिरते जा रहे हैं। जा रहे हैं। ईरान पर हमला बोलने और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की टारगेट किलिंग से पहले ट्रम्प ने कांग्रेस यानी अपनी देश की संसद से इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद हुए तमाम सर्वेक्षणों के अनुसार, अधिकांश अमेरिकी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विरोध में हैं। 2026 के मध्यावधि चुनावों को देखते हुए इन सर्वेक्षणों के राजनीतिक प्रभाव काफी गहरे और दूरगामी हो सकते हैं। ये राष्ट्रपति ट्रम्प की अपनी पार्टी के भीतर भी असर डाल रहे हैं।मेरिस्ट पोल के एक सर्वे के अनुसार, 56% अमेरिकी ईरान में सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हैं, जबकि 44% इसका समर्थन करते हैं। सीएनएन के सर्वे में 59% अमेरिकी लोगों ने ईरान पर हमलों के फैसले को गलत बताया है। रॉयटर्स के सर्वे में 43% लोगों ने इन हमलों का विरोध किया, जबकि केवल 27% ने इसका समर्थन किया। लगभग इसे लेकर 29% अनिश्चित थे। यूजीओवी के सर्वेमें 48% लोगों ने हमलों को नामंजूर किया, जबकि 37% ने इसे सही माना। अमेरिका का विपक्षी दल डेमोक्रेट्स में में लगभग 86% और निर्दलीय लगभग 61% मुख्य रूप से युद्ध के खिलाफ हैं, जबकि ट्रम्प की अपनी रिपब्लिकन के नेता (84%) बड़े पैमाने पर इसका समर्थन कर रहे हैं। मजे की बात है कि अमेरिका का युवा वर्ग युद्ध का सबसे बड़ा विरोधी है। 18-29 वर्ष के 64% युवा सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हैं। ईरान में अमेरिकी थल सेना भेजने के विचार का कड़ा विरोध हो रहा है, जहां 60% अमेरिकी इसके खिलाफ हैं। इन सर्वेक्षणों में दिख रहा भारी विरोध रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरा बन

सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो डेमोक्रेट्स और निर्दलीयों का गठबंधन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और संभवतः सीनेट पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। ट्रम्प के अपने कट्टर समर्थक आधार मेगा में भी विभाजन देखा जा रहा है। जहां 90% कट्टर समर्थक हमलों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं इस समूह का 'युद्ध-विरोधी' धड़ा इसे ट्रंप के 'अंतहीन युद्ध' को खत्म करने के वादे के खिलाफ मान रहा है।

अधिकांश अमेरिकी जनता ईरान पर किए गए हमले के खिलाफ है। सर्वे के नतीजे यही कह रहे है। बिना किसी ठोस वजह से ईरान पर किया गया हमला ट्रम्प के लिए मुसीबत बन सकता है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि महंगाई और बढ़ती है, तो ट्रम्प के लिए अपनी लोकप्रियता बनाए रखना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने कीमतें कम रखने का वादा किया था। दस्तक टाइम्स की एक रिपोर्टखाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण ईधन की कीमतें बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि महंगाई और बढ़ती है, तो ट्रम्प के लिए अपनी लोकप्रियता बनाए रखना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने कीमतें कम रखने का वादा किया था। सर्वेक्षणों के दबाव में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने के लिए युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव पर मतदान कर रही है। यह ट्रम्प के भविष्य के सैन्य निर्णयों पर कानूनी अंकुश लगा सकता है। वर्जीनिया जैसे राज्यों में, जहां सैन्य परिवारों की संख्या अधिक है, युद्ध एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है। सैन्य हताहतों की संख्या बढ़ने पर मतदाताओं की नाराजगी रिपब्लिकन

उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ सकती है।कई अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें 'कांग्रेस द्वारा अनधिकृत युद्ध' करार दिया है। आलोचकों का तर्क है कि यह अमेरिकी कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून (ईरान की संप्रभुता) का उल्लंघन है। ट्रम्प प्रशासन ने हमलों के लिए अलग-अलग कारण दिए हैं, जिनमें परमाणु हथियारों को रोकना, 'आसन्न खतरे' को टालना और शासन परिवर्तन शामिल हैं। इन दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में ऐसे किसी तत्काल खतरे या परमाणु हथियार कार्यक्रम के सक्रिय होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले थे।दक्षिणी ईरान के मीनाब में एक प्राथमिक स्कूल पर हुए हमले, जिसमें बच्चों सहित कई नागरिक मारे गए, ने भारी आक्रोश पैदा किया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी नागरिक ठिकानों और शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाने की आलोचना की है। आलोचकों का मानना है कि इन हमलों से पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल सकती है, जैसा कि 2003 के इराक युद्ध के समय हुआ था। ईरान द्वारा बहरीन, कुवैत और कतर जैसे पड़ोसी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर की गई जवाबी कार्रवाई ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन विरोधियों का आरोप है कि ट्रम्प इन हमलों का उपयोग आगामी चुनावों या अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं।उधर ईरान युद्ध पर अमेरिकी हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी न लेने के मुद्दे पर अमेरिकी राजनीति दो स्पष्ट गुटों में बंटी हुई है। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि 'यह हमला असंवैधानिक और अवैध है।' डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने इस कार्रवाई को राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग बताया है। डेमोक्रेट्स हाउस लीडर हाकीम जेफरीज ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इस 'युद्ध' के लिए स्पष्ट औचित्य और योजना पेश करे। सिनेटर टिम केन ने इन हमलों को एक 'बड़ी गलती' बताया और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित करने के लिए 'युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव' का नेतृत्व कर रहे हैं।

डेमोक्रेट्स का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, युद्ध की घोषणा करने की शक्ति केवल कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। जबकि ज्यादातर रिपब्लिकन नेता ट्रम्प के समर्थन में खड़े हैं और इसे एक आवश्यक कार्रवाई मान रहे हैं। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि ईरान अपने 'बुरे कार्यों' का परिणाम भुगत रहा है और उन्होंने हमलों को सही ठहराया।विदेशी मामलों की कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास्ट ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने 'आसन्न खतरे' से निपटने के लिए अपने संवैधानिकअधिकार का उपयोग किया है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का मानना है कि यह ईरान और उसके समर्थित समूहों के खिलाफ अरब और यूरोपीय देशों को एकजुट करने का एक मौका है। रिपब्लिकन इसे 'युद्ध' के बजाय एक 'सीमित सैन्य अभियान' यानी एयर स्ट्राइक कह रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ रिपब्लिकन सांसद अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं। थॉमस मैसी और वारेन डेविडसन ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। मैसी ने कहा कि भले ही ईरान दुश्मन है, लेकिन यह हमला 'संवैधानिक तरीके' से नहीं किया गया है। ब्रिनन सेंटर जैसे कई संवैधानिक विशेषज्ञों का तर्क है कि 1973 का वॉर पॉवर एक्स्ट राष्ट्रपति को बिना मंजूरी के केवल आत्मरक्षा या आपातकालीन स्थिति में ही सेना भेजने की अनुमति देता है। चूंकि कोई 'तत्काल हमला' नहीं हुआ था, इसलिए यह कानून का उल्लंघन है। उधर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी विशेष रूप से नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने को लेकर इन हमलों की कानूनी वैधतापर सवाल उठाए हैं।

परिवर्तन का दशक

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बदलता उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश ने पिछले नौ वर्षों में शासन, विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने कानून-व्यवस्था, निवेश और पर्यटन में नई दिशा प्राप्त करने का प्रयास किया है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के नौ वर्ष और दूसरी पारी के चार वर्ष' उत्तर प्रदेश, जो कभी कानून-व्यवस्था, अविकास और प्रशासनिक चुनौतियों के लिए चर्चा में रहता था, पिछले नौ वर्षों में एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरा है। वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तब उनके सामने प्रदेश को विकास, निवेश, सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता के नए रास्ते पर ले जाने की बड़ी चुनौती थी। दिनांक 19 मार्च 2026 को नौ वर्षों के

कार्यकाल और दूसरी पारी के चार वर्ष पूरे होने के बाद, उत्तर प्रदेश की तस्वीर में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव दिखाई देते हैं। कानून-व्यवस्था में बड़ा बदलाव-उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना रहा है। 2017 से पहले प्रदेश में अपराध और माफिया गतिविधियों को लेकर अक्सर आलोचना होती थी। योगी सरकार ने माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्यवाही की नीति अपनाई। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्यवाही और पुलिस की सक्रियता ने कानून के प्रति डर और भरोसा दोनों स्थापित करने का प्रयास किया। राज्य सरकार का दावा है कि अपराध दर में कमी आई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई विशेष कदम उठाए गए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्पलाइन और पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत किया गया। निवेश और औद्योगिक विकास- उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए योगी सरकार ने निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2003 के माध्यम से राज्य में लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। राज्य में औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और नए औद्योगिक क्षेत्रों का विका

स किया जा रहा है। उत्तरप्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना से प्रदेश को रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में काम चल रहा है। बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास-

पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में सड़क, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश को वैश्विक कनेक्टिविटी देने की दिशा में एक बडा कदम माना जा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का विस्तार योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को भी विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण वाराणसी में एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सामने आया। इससे काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच आसान हुई और वाराणसी में पर्यटन गतिविधियों में बड़ा इजाफा हुआ। इसी प्रकार अयोध्या राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के व्यापक विकास कार्यों ने प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाया है। गरीब कल्याण और सामाजिक योजनाएं योगी सरकार ने गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाओं को प्राथमिकता दी। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना को राज्य में बड़े पैमाने पर लागू किया गया। गरीब परिवारों को आवास, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य

बीमा और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान भी सरकार ने मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से लोगों को राहत देने का दावा किया। शिक्षा और युवा अवसर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पहलें की गई। सरकारी स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया गया। तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए गए। युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को भी तेज करने का प्रयास किया गया। डिजिटल प्रशासन और पारदर्शिता योगी सरकार ने

प्रशासन को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। इंटीग्रेटेड ग्रीवंस रिड्रेसल सिस्टम (IGRS) जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकते हैं। दूसरी पारी के चार वर्ष वर्ष 2022 में योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि लंबे समय बाद किसी मुख्यमंत्री को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला। दूसरी पारी के चार वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे, निवेश और धार्मिक पर्यटन के बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को भी जारी रखा गया है।

चुनौतियां और आगे की राह- हालांकि सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ कई चुनौतियां भी बनी हुई हैं। बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र की समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मुद्दे अभी भी चर्चा में रहते हैं। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, उद्योगों को बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की दिशा में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। अतः ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के नौ वर्ष और दूसरी पारी के चार वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए एक परिवर्तनकारी दौर के रूप में देखे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे का विस्तार, निवेश आकर्षित करने के प्रयास और धार्मिक पर्यटन के विकास ने राज्य की पहचान को नई दिशा देने का प्रयास किया है। यदि आने वाले वर्षों में ये पहलें लगातार आगे बढ़ती हैं और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का संतुलित समाधान किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था और विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

योगी मॉडल का वैश्विक डंका

यूपी को मिले एक लाख करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव
जापान, सिंगापुर से युपी को मिला बड़ा निवेश
बीते नौ सालों का सकारात्मक संदेश दुनिया में पहुंचा
नौजवानों के कौशल को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी

उप्र की लगातार बदलती हुई छवि के कारण अब भगवा रंग विदेश में भी चटक होता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जापान और सिंगापुर गए प्रतिनिधिमंडल के साथ यूपी सरकार को एक लाख करोड़ रूपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह प्रस्ताव यूपी की बढ़ती हुई साख की वजह से मिला है। यूपी में बेहतर होती कानून-व्यवस्था का ही परिणाम है कि अब विदेशों में भी योगी सरकार के प्रति निवेशकों में विश्वास बढ़ गया है। अगस्त में जापान और सिंगापुर के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी अपने संभावित यूपी के दौरे पर आएगा ताकि वह इन निवेष के प्रस्तावों को मूर्त रूप दे सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रान्त में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि चार दिवसीय सिंगापुर और जापान यात्रा के दौरान यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के बारे में बहुत सकारात्मक भाव है। उत्तर प्रदेश ने विगत नौ वर्षों में जो कदम उठाए हैं, उसका सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुँचा है। इस सकारात्मक भाव का लाभ उत्तर प्रदेश में हमारी टीम लेगी। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के 'स्केल को स्किलिंग' में बदलने तथा राज्य व स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगार से जोड़ने में अपना योगदान देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चार दिनों की यात्रा में उन्होंने अनेक महानुभावों के साथ मुलाकात की। जी-टू-जी, जी-टू-बी तथा बी-टू-बी लेवल की लगभग 60 से अधिक बैठकें व रोड शो इस दौरान सम्पन्न हुए। सिंगापुर, टोक्यो और यामानाशी प्रान्त में हुए रोड शो में लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन, सीईओ ने प्रतिभाग किया। उन्हें सिंगापुर, टोक्यो और यामानाशी में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करने का अवसर भी मिला।

यामानाशी प्रान्त सहित जापान से उत्तर प्रदेश को 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 90 हजार करोड़ रुपये के एमओयू सम्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार सिंगापुर से उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें 60 हजार करोड़ रुपये के एमओयू सम्पन्न हुए हैं। इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के अन्य विभाग इन निवेश प्रस्तावों व एमओयू को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर में आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सिटी, लॉजिस्टिक्स, सेमीकण्डक्टर, टूरिज्म, फिनटेक, मिडटेक, डीपटेक जैसे मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई। जीआईसी, टेमासेक, यूजीएस, गूगल, ब्लैक स्टोन आदि सिंगापुर बेस्ड कम्पनियाँ उत्तर प्रदेश में अपनी भागीदारी आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। योगी ने कहा कि यहाँ के विदेश मंत्री, आर्थिक मामलों के मंत्री और उपमंत्री, यामानाशी प्रान्त के गवर्नर और उप गवर्नर से भी सकारात्मक वार्ता हुई। यहाँ हमने लॉजिस्टिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सीबीजी, सोलर, टूरिज्म के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर की प्रमुख कम्पनियों-सुजुकी, हॉण्डा तथा सुमितोमो, यूनिक्लो जैसी कम्पनियों और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो) के चेयरमैन के साथ बैठक की। यामानाशी प्रान्त की गवर्नमेंट ने बहुत सकारात्मकता के साथ इनमें अपना योगदान दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे डेलीगेशन को यामानाशी गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लाण्ट की विजिट करवायी गयी। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे समृद्ध एवं पर्याप्त जल संसाधन मौजूद है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के उत्पादन की व्यापक

सम्भावनाएं हैं। यामानाशी प्रान्त उत्तर प्रदेश को उस प्रकार की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने और हमारे प्रदेश के युवाओं को इसका प्रशिक्षण देकर उनकी स्किलिंग में अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर में हमने अपनी टीम के साथ वहां के एक हाई क्लास स्किलिंग सेण्टर 'आईटीई' का अवलोकन किया है। हमने वहां पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल (एमआरओ) की कार्यवाही देखी है। हमने यह भी देखा है कि कार्गो की दृष्टि से वेयर हाउसिंग किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है। हमारा यह भ्रमण बहुत पॉजिटिव रहा है। हमने उन लोगों को उत्तर प्रदेश में विशेषकर यहां के 5वें इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा के लिए भी आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लाण्ट भी देखा और इसके उपरान्त सुपर हाई-स्पीड ट्रेन का निरीक्षण करने के साथ ही, उसमें यात्रा भी की। यह ट्रेन 2 मिनट के कम समय में ही 500 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। हम लोगों ने 120 किलोमीटर लम्बी यात्रा को कुछ ही मिनटों में तय कर लिया। यह जापान मॉडल की सुपर हाई-स्पीड मैग्लेव ट्रेन है। जापान में भी यह एक रोमांच का विषय बनी हुई है। सीएम ने कहा कि

जापान और उत्तर प्रदेश के मध्य एमएसएमई क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सेलिंग तथा अन्य मुद्दों पर सहयोग के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई है। हम इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जापान के निवेशकों के लिए एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। इसके लिए यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भूमि आवंटन की कार्यवाही हुई है। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण आज दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आना चाहते हैं। यामानाशी के गवर्नर आगामी अगस्त में जापान के 200 सीईओ के साथ उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। यह सभी उत्तर प्रदेश

की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कार्य करने के इच्छुक हैं। इसी प्रकार सिंगापुर का एक बिजनेस डेलीगेशन उत्तर प्रदेश आने को उत्सुक है। वह उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करना चाहते हैं। हमने इस सम्बन्ध में अभी से अपनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। हमारा प्रयास है कि समयबद्ध तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें और इन्हें जमीनी धरातल पर उतार सकें। यह उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के प्रयासों में मील का पत्थर साबित होंगे।

> ***"यामानाशी के गवर्नर आगामी अगस्त में जापान के 200 सीईओ के साथ उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। यह सभी उत्तर प्रदेश की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कार्य करने के इच्छुक हैं। इसी प्रकार सिंगापुर का एक बिजनेस डेलीगेशन उत्तर प्रदेश आने को उत्सुक है। वह उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करना चाहते हैं। हमने इस सम्बन्ध में अभी से अपनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।"***

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने यह देखा है कि बेहतर लॉ एण्ड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की अच्छी स्थिति तथा टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से उत्तर प्रदेश में हुए ट्रांसफॉर्मेशन के कारण दुनिया हम पर ट्रस्ट करती है। हमने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में 'टॉप अचीवर स्टेट' के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्केल, लैण्ड बैंक और निवेश के लिए सेक्टोरल पॉलिसीज मौजूद हैं। हमारे लिए स्वाभाविक रूप से यह एक नई शुरुआत होगी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के राज्य में आने और निवेश होने से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नई सम्भावनाओं के द्वार खुलेंगे। युवाओं को इसमें पारंगत कर उनकी स्किलिंग करने का अवसर भी प्राप्त होगा। प्रदेश की ट्रेण्ड मैन पावर दुनिया के किसी भी देश में जाकर बेहतर परिणाम दे सकती है। यहां होने वाले डेढ़ लाख करोड़ रुपये के एमओयू जब धरातल पर उतरेंगे, तो 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की सम्भावना साकार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर तथा जापान के मिशन से जुड़े अधिकारियों, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त और उनकी टीम तथा जापान में भारत की राजदूत और उनकी टीम ने बहुत सकारात्मक तरीके से पहले से ही हमारी टीम के साथ जुड़कर सभी तैयारियां की थीं। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।

चुनावी लोक-लुभावने वादों से दूर,

मिशन 2027-यूपी बजट में विकास का रोडमैप और आत्मविश्वास की झलक

बिना मुफ्त की सौगात के चुनाव की तैयारी

उप्र में कुछ माह बाद माहौल चुनावी हो जाएगा। नवंबर आते-आते टिकट पाने के लिए दिल्ली से लेकर नागपुर तक माननीयों के चक्कर बढ़ जाएंगे। योगी सरकार ने चुनाव में जाने से पहले उन बिन्दुओं पर फोकस किया है जो सीधे जनता से जुड़ते है। बीते 11 फरवरी को विधान सभा में सरकार ने अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में सरकार ने दो लाख करोड़ रूपए की व्यवस्था योजनाओं को पूरा करने और 44 हजारा करोड़ की नई योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की है। आम तौर पर चुनाव में जाने से पहले सरकार बजट में लोक लुभावनी योजनाओं की घोषणा करती है। योगी सरकार ने इससे परहेज किया और योजनाओं को पूरा करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इससे स्पष्ट है सरकार अगले विधान सभा चुनाव को लेकर काफी आष्वस्त है। जनता के बीच कोई नाकारात्मक छवि अभी सरकार को दिखाई नहीं पड़ रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश ने विगत 9 वर्षों के दौरान अपना परसेप्सन बदलने में सफलता प्राप्त की है। राज्य ने पॉलिसी पैरालिसिस से उबरकर अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। यह बजट इन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है। विगत 9 वर्षों में प्रदेश का बजट तीन गुना से अधिक बढ़ा है। आज 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। 'सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम तथा नकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश' के लिए समर्पित यह बजट नव वर्ष के नवनिर्माण की नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की हाइलाईट्स के अनुसार, 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गयी है। 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए है। परिसम्पत्तियों के नवनिर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट तथा अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार सृजन होता है। विगत 9 वर्षों में वर्तमान सरकार का 10वां बजट है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में कर चोरी, लीकेजेज आदि को रोक कर कुशल वित्तीय प्रबन्धन से प्रदेश को बीमारू राज्य से अर्थव्यवस्था का ब्रेक-थ्रू तथा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता 30 प्रतिशत से अधिक थी, उसे हम 27 प्रतिशत लाने में सफल हुए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसे 23 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। भारतीय रिर्जव बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता उसकी जीएसडीपी की 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जिसने अपने वित्तीय प्रबन्धन को एफआरबीएम की तय सीमा के अधीन रखा है। यह हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश वेलफेयर व इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ प्रत्येक सेक्टर में ऊंचाईयों को

> *प्रदेश में 'स्टेट डाटा अथॉरिटी' का गठन किया जाएगा, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस तथा अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेण्टर क्लस्टर की स्थापना का प्राविधान, मेडटेक व डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा से स्किल्ड युवा को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे*

, योजनाओं को पूरा करने पर जोर

प्राप्त करते हुए विकास के नये प्रतिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राज्य देश की टॉप-थ्री अर्थव्यवस्था में एक है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.24 प्रतिशत से कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2017 से पूर्व बेरोजगारी दर 17 से 19 प्रतिशत तक थी। वर्तमान बजट की सोच युवाओं के प्रति समर्पित है। प्रदेश में होने वाली ग्रोथ युवाओं के रोजगार से सम्बन्धित होनी चाहिए। इस पर ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी योजनाओं के अन्तर्गत स्थानीय उद्यमियों को ट्रेण्ड किया जा रहा है। निवेश की नई योजनाओं के साथ प्रदेश को इन्वेस्टमेण्ट डेस्टीनेशन तथा इम्प्लॉयमेण्ट जेनरेटर के रूप में बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अक्सर देखने को मिलता था कि अलग-अलग विभाग अलग-अलग समय में अलग-अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। वर्तमान सरकार ने तय किया कि प्रदेश में 'स्टेट डाटा अथॉरिटी' का गठन किया जाएगा। यह अथॉरिटी रियल टाइम डाटा और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। आज के बजट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से सम्बन्धित अनेक घोषणाएं हुई हैं। आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस तथा अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेण्टर क्लस्टर की स्थापना का प्राविधान किया गया है। मेडटेक व डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा से स्किल्ड युवा को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में आईटी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्राविधान किये गये हैं। 'उत्तर प्रदेश ए0आई0 मिशन' की शुरूआत की जा रही है। प्रदेश में एआई सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस, और एआई डाटा लैब्स तथा साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेण्टर की स्थापना हेतु बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

किसी मुख्यमंत्री को 10 वां बजट प्रस्तुत करने का यह प्रथम अवसर

2 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि कैपिटल एक्सपेंडीचर में

> *प्रदेश में एआई सेण्टरआफ एक्सीलेंस, एआई डाटा लैब्स तथा साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेण्टर की स्थापना हेतु बजट में धनराशि की व्यवस्था*

सिटी इकोनॉमिक जोन, एससीआर, काशी-मीरजापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज-चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर-झांसी इकोनॉमिक जोन क्लस्टर डेवलपमेण्ट की नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के प्राविधान इस बजट में किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' में प्रदेश की रैंकिंग 13-14 पर थी। वर्तमान सरकार ने पहले 3 वर्षों में इसे दूसरे नम्बर पर लाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश ने चीफ अचीवर्स स्टेट के रूप में स्वयं को स्थापित किया। अब जन-विश्वास सिद्धान्त के रूप में निवेशकों के लिए 'सिंगल विण्डो' के माध्यम से लाइसेंसिंग, पंजीकरण आदि की कार्यवाही को अधिक सहज व सरल बनाने की दिशा में कदम उठाये गये हैं। प्रदेश में डिजिटल इण्टरप्रेन्योरशिप योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में बजट में प्राविधान किये गये हैं। इन कार्यों में हमें सफलता तब प्राप्त हुई है, जब प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का वातावरण निर्मित किया गया।

ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का बढता कारवां

सुबह जब आम आदमी की जिंदगी रफ्तार पकड़ती है, उसी समय कुछ ऐसे हाथ भी सक्रिय हो जाते हैं जो अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए काम करते हैं। यही कहानी है ममता चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके मुखिया राजीव कुमार मिश्रा की। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा संगठन जिसने कम समय में सेवा, संवेदना और समर्पण की मिसाल कायम की है।यह संस्था केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक विचार है, वह विचार जो कहता है कि समाज का विकास तभी संभव है जब सबसे कमजोर व्यक्ति अथवा समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हर व्यक्ति भी मुख्यधारा से जुड़ सके।

ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की नींव शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पेशेवरों और समाजसेवियों के समूह ने रखी, जिनके लिए समाज सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी उठाना ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का संकल्प है।

ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से लेकर शहरी झुग्गियों तक, संस्था का उद्देश्य स्पष्ट है- जागरूकता, अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से समाज में स्थायी परिवर्तन।

सीडब्ल्यूडी, एनसीडब्ल्यू, एचआरडी, रोजगार सृजन, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा के मूल्य-इन सभी क्षेत्रों में ट्रस्ट सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

गरीब असहायों वंचितों के लिए नई सुबह

ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का सबसे बड़ा सपना है कि अशिक्षित, बेरोजगार और सड़कों पर कचरा बीनने वाले बच्चों को सशक्त बनाना। कल्पना कीजिए उस बच्चे की, जो कल तक सड़क पर था। आज किताब थामे स्कूल जा रहा है। यही परिवर्तन ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का वास्तविक लक्ष्य है। संस्था न केवल शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी बनाने का प्रयास भी कर रही है। ट्रस्ट का मूल मंत्र है सेवा बिना भेदभाव जाति, धर्म, रंग या पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर, संस्था गरीबों, जरूरतमंदों और निराश्रितों के लिए कार्य कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल एवं अध्ययन केंद्रों की स्थापना। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियमित निःशुल्क चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान।

स्वास्थ्य और जागरूकता का अभियान

पिछले कई वर्षों से ट्रस्ट ने कई चिकित्सा शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित किए। प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के मुखिया राजीव मिश्र द्वारा दिव्यांगों को हजारों की संख्या में ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन,वैसाखी इत्यादि दिव्यांग उपकरण वितरति किए जाते है। अस्पतालों में बडी संख्या में स्ट्रेचर, व्हील चेयर इत्यादि वितरित किए जाते है। संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष शीत लहर के दौरान प्रत्येक गरीब, असहाय, वृद्धजनों एवं बुजुर्ग मातृशक्तियों को लाखों की संख्या में कंबल वितरण कर शीत लहर के प्रकोप से बचाने का प्रयास किया जाता है। कोरोना के पहले लाकडाउन में 65 दिन का कोविड राशन वितरण अभियान चलाकर लगभग 1 लाख 65 हजार व्यक्तियों को राशन तथा अन्य जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई गई। कोरोना के दूसरी खतरनाक लहर की विपदा में आक्सीजन 1277, कोविड औषधि 12700, वेपोराइजर मशीन तथा 95000 एन 95 मास्क व सेनेटाइजर 568000 व्यक्तियों को भेंट किया गया। साथ ही सरकारी अस्पतालों, थानों, कार्यालयों में भारी मात्रा में कोविड सामग्री पहुचाई गयी। यह महाअभियान 60 दिनो तक चलाया गया। इसके साथ ही सम्पूर्ण लखनऊ शहर कोविड मुक्त सेनेटाइजेशन महाभियान के अंतर्गत पूरे लखनऊ शहर में 15 दिन तक निरन्तर 11 रथों के माध्यम से सेनेटाईजेशन

किया गया।कोरोना काल में भी संस्था ने सक्रिय रहकर स्वास्थ्य जागरुकता, सहायता और रोजगार से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए। डॉक्टरों की टीम, वकीलों का सहयोग, शिक्षाविदों का मार्गदर्शन और समाजसेवियों का समर्पण-इन सभी ने मिलकर सेवा की एक मजबूत नीव रखी।

ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव मिश्रा कहते हैं

उत्तर प्रदेश की धरती पर सेवा का अब तक का समय हमारे लिए केवल एक औपचारिक उपलब्धि नहीं, बल्कि विश्वास, प्रतिवद्धता और सामाजिक उत्तरदायित्व की एक सतत यात्रा का महत्वपूर्ण पढ़ाव है।

इस एक वर्ष में हमने सीखा कि बदलाव केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि संवेदनशील सोच और निरंतर प्रयास से आता है। हम ईश्वर के प्रति कृतज है, जिन्होंने हमें सही दिशा और शक्ति प्रदान की। हमारे सलाहकार मंडल, सहयोगी संस्थाएं, समर्पित कार्यकर्ता, डॉक्टरों और शिक्षाविदों की टीम, दानदाता एवं शुभचिंतक इन सभी के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। हमारा संकल्प है कि जाने वाले वर्षों में हम किथा, स्वास्थ्य, महित्य सशकिकरण, कोहल विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में जैस एवं स्थायी पहल करेंगे। हमाला उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है। हम चाहते हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके।

यह सफर अभी शुरुआत है। हम सेवा, पारदर्शिता और समर्पण के मूल्यों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जरूरतमंद तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब तक की उपलब्धियां केवल आरंभ है। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट आने वाले समय में योजनाबद्ध और संरचित तरीके से बड़े स्तर पर कार्य करने की दिख में अग्रसर है। संस्था की भविष्य को प्राथमिकताएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल एवं अध्ययन केंद्रों की स्थापना। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियमित निःशुल्क चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जागरुकता अभियान। कौशल विकास एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही महिला और बाल सकिकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं सहायता परियोजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास मॉडल ठेकर करना है। ममता चौरिटेबल ट्रस्ट की यह यात्रा किसी एक संस्था की कहानी नहीं, बल्कि उस सकारात्मक सोच का प्रतीक है जो मानती है दृढ़ इण्दे, सही दिशा और सामूहिक प्रयास से हर बदलाव संभव है। लखनऊ से प्रारंभ हुई यह सेवा की ज्योति अब पूरे उत्तर प्रदेश में आशा, सम्मान और अवसर की रोशनी फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

केरल अब 'केरलम'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'केरल' राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधान सभा को केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक एक विधेयक भेजेंगे।

केरल राज्य विधान सभा की राय प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और संसद में 'केरल' राज्य का नाम 'केरलम' करने के लिए केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त की जाएगी।केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को 'केरल' राज्य का नाम 'केरलम' करने का एक प्रस्ताव पारित किया, जो इस प्रकार है- "हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में 'केरलम' है। 1 नवंबर, 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। केरल पिरवी दिवस भी 1 नवंबर को है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों के लिए संयुक्त केरल के गठन की एक मजबूत मांग रही है लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम 'केरल' दर्ज है। यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्रीय सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नाम को 'केरलम' में संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील करती है।"इसके बाद, केरल सरकार ने भारत सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम 'केरल' से 'केरलम' करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। संविधान

> *केरल राज्य विधान सभा की राय प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और संसद में 'केरल' राज्य का नाम 'केरलम' करने के लिए केरल (नाम परिवर्तन)*

का अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के नामों के परिवर्तन के लिए प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है।'केरल' राज्य का नाम 'केरलम' करने के मामले पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विचार किया गया और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री की मंजूरी से, 'केरल' राज्य का नाम 'केरलम' करने के लिए कैबिनेट के लिए मसौदा नोट को टिप्पणियों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग को प्रसारित किया गया था। विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय ने 'केरल' राज्य का नाम 'केरलम' करने के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है।

सतर्कता, समन्वय के साथ काम पूरा करना ही बाढ़ प्रबन्धन की मूल कुंजी

सभी तटबंधों और बैराजों पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर प्रदेश में सम्भावित बाढ़ और अतिवृष्टि की चुनौतियों के दृष्टिगत व्यापक तैयारी और प्रभावी समन्वय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जितनी बेहतर तैयारी होगी, उतनी ही तेजी और सफलता से चुनौती का समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने बाढ़-अतिवृष्टि पूर्व प्रबन्धन की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी तटबन्धों, ड्रेनों और संवेदनशील स्थानों की समयबद्ध मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और निगरानी को अनिवार्य बताया।

उन्होंने निर्देश दिये कि सतर्कता, समन्वय और तय समयसीमा में काम पूरा करना ही सुरक्षित बाढ़ प्रबन्धन की मूल कुंजी है। प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन अनिल गर्ग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गंगा, सरयू (घाघरा) राप्ती, रामगंगा, गंडक, यमुना, गोमती और सोन नदी बेसिन के आस-पास के जनपद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। नदी-पट्टी और वर्षा पैटर्न का विश्लेषण करते हुए इस वर्ष 12 जनपदों में 18 तटबंधों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है, जिनकी कुल लम्बाई 241.58 किमी है। 11 जनपदों के 19 तटबंधों को अति संवेदनशील चिन्हित किया गया है, जिनकी कुल लम्बाई 464.92 किमी है। इन सभी स्थानों पर अग्रिम सुरक्षा कार्य प्राथमिकता पर संचालित हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जल-निकासी को सुचारु रखने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रेनों की सफाई और ड्रेजिंग कराई जा रही है। विभाग के अधीन कुल 10,727 ड्रेन हैं, जिनकी संयुक्त लम्बाई 60,047 किमी है। कई महत्वपूर्ण रूटों की सफाई पूरी हो चुकी है और शेष कार्य तय समय में पूरे किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित ड्रेजिंग परियोजनाएं जनपदवार लागू की जा रही हैं, जिससे नदी प्रवाह सुधरेगा और तटीय इलाकों में जलभराव कम होगा। इसके साथ ही, वर्ष 2026 की सम्भावित बाढ़ स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई सुरक्षा परियोजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं, जिनके परीक्षण और अनुमोदन की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तटबंधों और बैराजों पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ड्रोन-मैपिंग, वॉटर लेवल सेंसर और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय को और मजबूत बनाने के निर्देश दिये। जहां कहीं भी नदी की मेन स्ट्रीम में सिल्ट की अधिकता हो, नदी उथली हो, वहां ड्रेजिंग को प्राथमिकता दी जाए और नदी को चैनलाइज किया जाए। यदि ड्रेजिंग से समाधान होना सम्भव न हो, तभी तटबंध अथवा कटान निरोधी अन्य उपायों को अपनाया जाए।

> ***ड्रोन-मैपिंग, वॉटर लेवल सेंसर और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय को और मजबूत बनाने के निर्देश, जहां कहीं भी नदी की मेन स्ट्रीम में सिल्ट की अधिकता हो, नदी उथली हो, वहां ड्रेजिंग को प्राथमिकता दी जाए और नदी को चैनलाइज किया जाए***

भागवत ने समाज को जातियों में बांटने - बंटने पर चिंता जताई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं। वे कोई अरब से नहीं आए है। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटें, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। संघ प्रमुख भागवत 17 और 18 फरवरी को लखनऊ प्रवास पर थे।

संघ प्रमुख ने बढ़ती घुसपैठ पर कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। उन्हें रोजगार नहीं देना है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर कहा कि हिंदुओं के कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है। यह कम से कम 3 होनी चाहिए। जिस समाज में औसतन तीन से कम बच्चे होते हैं, वह समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं, उन्हें बताइए कि कम से कम तीन बच्चे पैदा करें। डॉ. भागवत ने कहा कि विवाह का उद्देश्य सृष्टि आगे चले, यह होना चाहिए, वासना पूर्ति नहीं। इसी भावना से कर्तव्य बोध आता है। उन्होंने कहा कि यदि यूजीसी यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगडे का कारण नहीं बनना चाहिए। समाज में अपने पन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए।

भागवत ने समाज को जातियों में बांटने और बंटने पर चिंता जताई

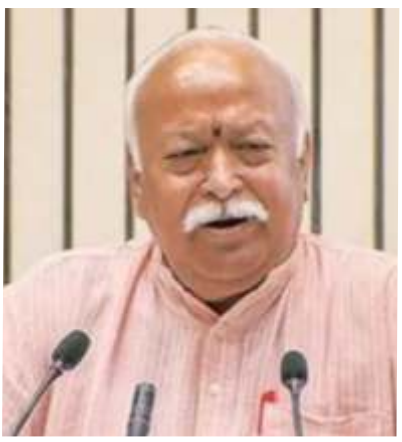

उन्होंने कहा कि हमें जाति के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जाति ऐसी चीज है, जिसे हम कई दशकों से समाप्त करने में लगे हैं, लेकिन ये जाति है कि जाती नहीं है। पहले दिन निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में सामाजिक सद्भाव बैठक में शिरकत की। करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव से जुड़े विषयों पर बैठक में शामिल समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के जवाब दिए। संघ प्रमुख ने कहा, अमेरिका और चीन जैसे देशों में बैठे कुछ लोग हमारी सद्भावना के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। इससे हमें सावधान रहना होगा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास समाप्त करना होगा। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना होगा। जातिवाद पर मोहन भागवत ने कहा, 500 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज शासन कर चले गए, लेकिन हिंदू धर्म संस्कृति इतनी मजबूत है कि उसे मिटा नहीं सके। जब इतने सालों में हिंदू धर्म का कोई कुछ नहीं बिगड़ सका तो कोई अब क्या बिगाड़ पाएगा। समाज में जो जाति की विषमता फैल रही है, उसे दूर करना होगा। यह किसी सरकार या संगठन का काम नहीं है, बल्कि इसे समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति को मिलकर करना होगा। अपनी बिरादरी के लोगों की शिक्षा और उन्नति का प्रयास करें। हर बिरादरी में अपना एक मित्र और परिवार बनाएं। आसपास के लोगों के साथ सद्भाव बनाएं। एसआईआर गाइडलाइंस पर मोहन भागवत ने कहा, कानून सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियों के झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। यूजीसी को लेकर एक पक्ष को लगता है कि ये हमारे खिलाफ है। दूसरे पक्ष को लगता है कि हमारे साथ है। सरकार नियम बनाती है। यदि किसी को वह अच्छा नहीं लगता है तो अपनी बात रखनी चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। जो नीचे गिरे हैं, उन्हें झुक कर ऊपर उठाना पड़ेगा। सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। संघ प्रमुख ने कहा, सद्भाव ना रहने से भेदभाव होता है। हम सभी एक देश, एक मातृभूमि के पुत्र हैं। मनुष्य होने के नाते हम सब एक हैं। एक समय भेद नहीं था, लेकिन समय चक्र के चलते भेदभाव की आदत पड़ गई है, जिसे दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन विचार धारा सद्भाव की विचारधारा है। जो विरोधी हैं, उन्हें मिटाना है, ऐसा हम नहीं मानते। एक ही सत्य सर्वत्र है। इस दर्शन को समझ कर आचरण में लाने से भेदभाव समाप्त होगा। मोहन भागवत ने कहा, घर-परिवार का आधार मातृशक्ति है। हमारी परंपरा में कमाई का अधिकार पुरुषों को था लेकिन खर्च कैसे हो, यह मातायें तय करती थी। मातृशक्ति विवाह के बाद दूसरे घर में आकर सभी को अपना बना लेती है। महिला को हमें अबला नहीं मानना है, वह असुर मर्दिनी है। हमने स्त्री की, प्रकृति की जो कल्पना की, वह बलशाली है। महिलाओं को आत्म संरक्षण का प्रशिक्षण होना चाहिए। पश्चिम में महिलाओं का स्तर पत्नी से है, हमारे यहां उन्हें माता माना जाता है। उनका सौंदर्य नहीं, वात्सल्य देखा जाता है।

नाथ संप्रदाय

नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता रही है समन्वय। इस परंपरा ने ना शेव, बौद्ध, तांत्रिक और लोक परंपराओं को जोड़कर एक व्यापक साधना-पद्धति विकसित की। यह पंथ न तो किसी एक ग्रंथ तक सीमित रहा, न किसी एक जाति तक। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और अन्य सिद्ध योगियों ने समाज को यह संदेश दिया कि मुक्ति का मार्ग बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि आत्मचेतना में है। उनके लिए मंदिर, मस्जिद, जाति, वर्ग सब गौण थे। प्रमुख था मनुष्य का अंतःकरण । मुस्लिम शासन काल और नव-मुसलमानों की पीड़ा जब भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सामाजिक कारणों से इस्लाम स्वीकार किया। इनमें से अधिकांश लोग निम्न या वंचित वर्गों से थे, जिन्हें हिंदू समाज में सम्मान नहीं मिल रहा था। उन्होंने यह आशा की थी कि इस्लाम उन्हें बराबरी, भाईचारा और सम्मान देगा। लेकिन वास्तविकता भिन्न थी। सत्ता पर अरब और तुर्क शासकों का वर्चस्व था। नव-मुसलमानों को अक्सर दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। उनके साथ भेदभाव समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसका स्वरूप बदल गया। वे न पूरी तरह पुराने समाज के रहे, न नए समाज में पूर्णतः स्वीकार हुए। इस दोहरे संकट ने उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित कर दिया। नाथ संप्रदायः शरणस्थली के रूप में ऐसे वातावरण में नाथ संप्रदाय फिर एक बार शरणस्थली बनकर उभरा। यह पंथ धर्मांतरण की राजनीति से परे था। यहां न तो हिंदू-मुसलमान का भेद था, न ऊंच-नीच की दीवार। नाथ योगियों के अखाड़े और आश्रम ऐसे स्थान बने, जहां पीड़ित मनुष्य बिना पहचान खोए शांति पा सकता था। कई नव-मुसलमानों और वंचित समुदायों को यहां आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन मिला। यह ऐतिहासिक तथ्य दर्शाता है कि नाथ परंपरा ने सदैव सामाजिक घावों पर मरहम लगाने का कार्य किया। घर वापसी और समकालीन संदर्भ आज जब संघ प्रमुख मोहन भागवत मुसलमानों के संदर्भ में "घर वापसी" जैसी बातें करते हैं, तो इतिहास हमें याद दिलाता है कि इस दिशा में सबसे ठोस आधार पहले से ही नाथ परंपरा में मौजूद है।

घर वापसी केवल धार्मिक पहचान बदलने का नाम नहीं हो सकता। यह सामाजिक सम्मान, सांस्कृतिक सुरक्षा और मानसिक संतुलन का प्रश्न है। नाथ संप्रदाय यह कार्य सदियों से करता आया है- बिना प्रचार, बिना दबाव और बिना राजनीति के। नाथ संप्रदाय और मानव चेतना का विज्ञान नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा योगदान मानव चेतना के क्षेत्र में है। योग, योगी आदित्यनाथ और नाथ परंपरा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश का नेतृत्व आज योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो स्वयं नाथ

पंथ के महंत हैं। जब उन्हें सत्ता सौंपी गई, तब यह अपेक्षा थी कि वे नाथ परंपरा के समन्वयी, करुणामय और मानवतावादी मूल्यों को शासन में उतारेंगे। यह दायित्व केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि वैचारिक भी था। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व, विशेषकर मोहन भागवत को भी यह मार्गदर्शन देना चाहिए था कि शासन का उद्देश्य सांस्कृतिक संतुलन हो, न कि एकांगी पुनरुत्थान। परंतु व्यवहार में यह अपेक्षा पूरी होती नहीं दिखती। शासन अधिकतर एक पक्षीय सांस्कृतिक विमर्श में उलझा दिखाई देता है। राष्ट्रीय संस्कृति की व्यापकता के स्थान पर संकीर्ण पहचान पर जोर बढ़ता गया है। ***नाथ परंपरा का मूल संदेश है-धर्म का सार समन्वय में है, विभाजन में नहीं। साधना का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, बल्कि समाज में संतुलन, करुणा और आत्मचेतना का विस्तार है।***

प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, ध्यान और समाधि जैसी साधनाओं के माध्यम से इस परंपरा ने मनुष्य की सुप्त शक्तियों को जाग्रत करने की विधियां विकसित कीं।

आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान और योग से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, तनाव कम होता है और रचनात्मकता बढ़ती है। लेकिन नाथ योगी यह सब सदियों पहले जानते थे। उनकी साधना केवल आत्मकल्याण तक सीमित नहीं थी। इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता था, नैतिकता

सुदृढ़ होती थी और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था। व्यक्तिगत महिमा और लोक कल्याण नाथ परंपरा ने कभी व्यक्तिगत महिमा और लोक कल्याण को अलग नहीं माना। उनके अनुसार, जो व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली होता है, वही समाज को दिशा दे सकता है। योगी अपने भीतर करुणा, साहस और विवेक विकसित करता है। यही गुण उसे सामाजिक कार्य के योग्य बनाते हैं। इसीलिए नाथ योगी केवल साधु नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी रहे हैं। वर्तमान नेतृत्व और वैचारिक शून्यता दुर्भाग्यवश, आज नाथ परंपरा की यह गहन दार्शनिक विरासत सत्ता और राजनीति में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है। स्वयं योगी आदित्यनाथ, नाथ पंथ के महंत होने के बावजूद, अपने संप्रदाय की मौलिक अवधारणाओं से अधिक जुड़ाव प्रदर्शित नहीं करते। उनकी राजनीति अधिकतर प्रशासनिक कठोरता और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण तक सीमित प्रतीत होती है। मानव क्षमता संवर्धन, आत्मिक विकास और सामाजिक समन्वय जैसे विषय उनके एजेंडे में प्रमुख नहीं दिखते। ऐतिहासिक विडंबना यह एक गहरी विडंबना है कि जिस परंपरा ने बौद्धों. नव-मुसलमानों और वंचितों को आश्रय दिया, उसी परंपरा का प्रतिनिधि आज सत्ता में होकर भी उस विरासत को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। नाथ संप्रदाय की आत्मा राजनीत्ति से कहीं बड़ी है। वह मनुष्य को जोड़ने की कला है, तोड़ने की नहीं। नाथ परंपरा से सीखने की आवश्यकता आज भारत फिर एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक अविश्वास और वैचारिक संकीर्णता बढ़ रही है। ऐसे समय में नाथ संप्रदाय की परंपरा हमें रास्ता दिखा सकती है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि:

धर्म का उद्देश्य विभाजन नहीं, समन्वय है। साधना का लक्ष्य केवल मोक्ष नहीं, मानव कल्याण है। संस्कृति की रक्षा तलवार से नहीं, करुणा से होती है। यदि आज का नेतृत्त्व नाथ पंथ की इस मूल चेतना को समझ ले, तो 'घर वापसी अपने आप हो जाएगी बिना दबाव, बिना नारे और बिना टकराव के। भारत को फिर से उसी प्रकाश-स्तंभ की आवश्यकता है, जो अतीत में उसे अंधकार से बाहर निकाल चुका है। नाथ संप्रदाय वह स्तंभ रहा है और आज भी बन सकता है, यदि हम उसकी आत्मा को पहचानने का साहस करें।

एक दशक में काफी बदल गया पश्चिम बंगाल का परिदृश्य

पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य 2016 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2021 और 2026 के चुनावों की तैयारी तक काफी बदल गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रभुत्व वाली राज्य की 294 सीटों वाली विधानसभा में वाम-कांग्रेस गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बढ़ती लोकप्रियता और टीएमसी के सुदृढ़ीकरण के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, जो क्षेत्रीय गतिशीलता, जनसांख्यिकी और मतदाता सूची में बदलाव से प्रभावित हैं

2016 में टीएमसी ने 2011 की वाम-विरोधी लहर को और मजबूत करते हुए 211 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। वाम मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन को केवल 32 सीटें मिलीं (गठबंधन के हिसाब से सीपीएम को 26 और कांग्रेस को 0), जिनमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद और घाटाल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कुछ सीटें शामिल थीं। बीजेपी को केवल 3 सीटें मिलीं, जो मुख्य रूप से दार्जिलिंग और शहरी बाहरी इलाकों में थीं, जो इसकी शुरुआती उपस्थिति का संकेत देती हैं। टीएमसी ने दक्षिण बंगाल (उदाहरण के लिए- दक्षिण 24 परगना में 31ध्31) और शहरी कोलकाता (11 में से अधिकांश सीटें) में शानदार जीत हासिल की, जबकि मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों और ग्रामीण हुगली में वामपंथियों की ताकत बनी रही। 2011 के परिसीमन के बाद 23 जिलों में 294 निर्वाचन क्षेत्रों को स्थिर किया गया, जिससे ज्डब् के ग्रामीण आधार को मजबूती मिली।

आर्थिक संकट - बढ़ता घाटा (2022-23 में 49,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,05,000 करोड़ रुपये का ऋण) - और अंतरिम बजट में किए गए तुष्टीकरण (उत्तरी बंगाल के विकास के बजाय मदरसा निधि का उपयोग) ने विभाजन को और गहरा कर दिया। उत्तर-दक्षिणी बंगाल का विभाजन और गहरा गया है, टीएससी 200 से अधिक सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, जबकि भाजपा गठबंधन के माध्यम से 100 से अधिक सीटों का लक्ष्य बना रही है। यह बदलाव पश्चिम बंगाल में वामपंथ के पतन से लेकर टीएमसी-भाजपा के द्विध्रुवीय चुनावी मुकाबले तक के परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें 2026 के चुनाव सीमित सीटों और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी पर निर्भर करेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पश्चिम बंगाल में इस वर्ष अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जिसमें 294 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।

2021- भाजपा की बड़ी सफलता और टीएमसी की मजबूत जीत

2021 के चुनावों ने एक बड़ा बदलाव ला दिया, जिसमें भाजपा ने हिंदुत्व-एनआरसी के मंच पर 77 सीटें जीतकर जबरदस्त बढ़त

हासिल की। उसने जंगलमहल (पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुरारू 30 सीटें) और उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी) में भी बढ़त बनाई। संदेशखाली जैसे मुद्दों और कोविड प्रबंधन में हुई गड़बड़ियों को लेकर सत्ता विरोधी लहर के बावजूद टीएमसी ने वापसी करते हुए 213 सीटें जीतीं। टीएमसी ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना) में दबदबा बनाए रखा और दक्षिण 24 परगना (31 सीटें), हावड़ा (16) और हुगली (18) में अपनी सीटें बरकरार रखीं। भाजपा ने सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जहां टीएमसी की कल्याणकारी योजनाओं ने उसे 30 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर दिलाए।

2026 का परिदृश्य

मतदाता सूची में नाम छांटने से चुनावी मैदानों की रूपरेखा बदल गई

मार्च 2026 तक, अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं, और 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। विशेष गहन संशोधन एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों से 63.66 लाख नाम (मतदाताओं के 10 प्रतिशत से अधिक) हटा दिए गए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों, मतुआ (नमशूद्र) क्षेत्र और अल्पसंख्यक जिलों की 125 से अधिक सीटों पर जनसांख्यिकी में बदलाव आया है। इसके प्रभावों में मतुआ और उत्तरी बंगाल के उन क्षेत्रों में बीजेपी की संभावित बढ़त शामिल है, जहां नाम हटाए गए हैं, और यह टीएमसी के अल्पसंख्यक गढ़ों जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा को चुनौती दे सकता है, जहां नाम हटाए जाने से भारी नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना (कुल 64 सीटें), पुरबा बर्धमान (16) और पुरबा मेदिनीपुर (16) जैसे जिलों में उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है, जहां राजकोषीय तनाव (अनुमानित 62,000 करोड़ रुपये का घाटा) विपक्षी चर्चाओं को बल दे रहा है।

क्षेत्रीय ध्रुवीकरण हुआ तेज

भाजपा ने सीमावर्ती और जंगलमहल क्षेत्रों में हिंदुओं के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के भय का फायदा उठाते हुए अपनी सीटें 3 से बढ़ाकर 77 कर लीं, जबकि टीएमसी ने मुस्लिम वोट बैंक (30-40 प्रतिशत वोट बैंक) को एकजुट करके इसका मुकाबला किया। 2011 के बाद परिसीमन ने सीमाएँ तय कर दीं, लेकिन 2026 के एसआईआर मतदाता सूची ने पुनर्निर्धारण का काम किया, जिससे मतुआ (नागरिकता के बाद) में भाजपा को मजबूती मिली और टीएमसी के कल्याणकारी प्रभुत्व की परीक्षा हुई।

सुप्रीमकोर्ट में बतौर अधिवक्ता पेश होने वाली ममता पहली सीएम

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हुईं और अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उपयोग त्रुटियों को दूर करने के बजाय पश्चिम बंगाल को निशाना बनानेष् और वैध मतदाताओं को हटाने के लिए किया जा रहा है। बनर्जी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया केवल मतदाताओं को बाहर करने के लिए की जा रही है, न कि उन्हें शामिल करने के लिए। उन्होंने कहा कि यह एसआईआर हटाने के लिए है, शामिल करने के लिए नहीं,ष् और आरोप लगाया कि लाखों मतदाताओं को ष्तार्किक विसंगतियोंष् के आधार पर गलत तरीके से चिह्नित किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा पैरवी की गई उनकी याचिका में कथित प्रक्रियात्मक चूकों की ओर इशारा किया गया है, जिसमें मतदाताओं को विसंगत के रूप में वर्गीकृत करने के कारणों का खुलासा न करना और चुनाव आयोग द्वारा वैध दस्तावेजों को अस्वीकार करना शामिल है।

बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि 58 लाख मतदाताओं के नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं और लगभग 88 लाख मतदाताओं को चिह्नित किया गया है, जबकि लगभग तीन लाख आपत्तियां अभी भी लंबित हैं, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 दिनों के भीतर निर्धारित है। भाषाई वास्तविकताओं पर प्रकाश डालते हुए, बनर्जी ने तर्क दिया कि सामान्य बंगाली उपनामों जैसे दत्ता और दत्ता, रॉय और रे, गांगुली और गांगुली को बेमेल माना जा रहा है।उनके अनुसार, उनकी कानूनी टीम ने कहा कि ये वर्तनी की गलतियाँ नहीं हैं। ये स्थानीय बोली के अंतर हैं जो पूरे भारत में होते हैं। एक बेटी शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और अपने पति का उपनाम इस्तेमाल करती है। वे (ईसीआई) उसका नाम हटा रहे हैं। क्या यह उसका नाम हटाने का कारण है?

पीएम-सूर्यघर योजना

सोलर पैनल से रोशन होंगे लाखों घर

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य देशभर में एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।

योजना का क्रियान्वयन और जिम्मेदार एजेंसी

इस संबंध में जानकारी देते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

बिजली बिल में राहत और आय का अतिरिक्त स्रोत- योजना के माध्यम से न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर उपभोक्ता उसे ग्रिड में बेचकर आय का अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र स्थापना पर सीधे उनके बैंक खाते में अधिकतम 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। एक किलोवाट क्षमता पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी अनुमन्य है। यह सब्सिडी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे लाभार्थी के

खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

ऑनलाइन आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं सरल रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित डिस्कॉम से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

स्थापना के बाद औपचारिकताएं और ऋण सुविधा

अनुमोदन मिलने के पश्चात सोलर पैनल स्थापित कर नेट मीटर की जानकारी एवं बैंक खाता विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त, 3 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र के लिए लगभग 7 % ब्याज दर पर बिना गारंटी ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आम नागरिकों को आर्थिक सहायता मिल सके।

पात्रता की शर्तें

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना, घर की छत सोलर पैनल के लिए उपयुक्त होना, वैध बिजली कनेक्शन होना तथा किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का पूर्व में लाभ न लिया होना आवश्यक है।

जरूरी दस्तावेज और संपर्क जानकारी

आवेदन के लिए आधार कार्ड, नवीनतम बिजली बिल, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी दस्तावेज हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यदिवस में परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा, कक्ष संख्या 111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में संपर्क कर सकते हैं। योजना को प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पोखरण से शक्ति का संदेश

भारतीय वायुसेना एक बार फिर अपनी अचूक क्षमता, अभेद्य सुरक्षा और सटीक प्रहार कौशल का शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। पोखरण के रेगिस्तानी क्षेत्र में 'वायुशक्ति 26' के तहत भारतीय आसमान में ताकत, गति और समन्वित मारक क्षमता का अद्भुत नजारा देखने को मिला । इस दौरान भारतीय वायुसेना ने सभी संचालन मानकों को सफलतापूर्वक परखा। अभ्यास के दौरान सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से नष्ट किया गया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि वायु सेना पूरी तरह से हर मिशन के लिए तैयार है। 'वायुशक्ति 26' को लेकर भारतीय वायुसेना ने पहली बार एक आधिकारिक वीडियो में एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की फायरिंग का दृश्य साझा किया है। इसमें वीडियो में एस-400 वायु रक्षा प्रणाली से लक्ष्य भेदते हुए देखा जा सकता है।यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइल जैसे बड़े हवाई खतरों को लंबी दूरी से ही नष्ट करने में सक्षम है। एस-400 प्रणाली अत्याधुनिक रडार और मिसाइल तकनीक से लैस है। यह एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रखने और उन्हें मार गिराने की क्षमता से लैस है।

वायुसेना के इस महत्वपूर्ण अभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, मिग-29, मिराज-2000 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। साथ ही सी-17, सी-130जे और सी-295 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान भी यहां उड़ान भरते दिखाई देंगे। वहीं, अपाचे हेलिकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, एलसीएच एमआई-17 जैसे हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। इस अभ्यास में 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं।

इस अभ्यास में हाल के ऑपरेशन 'सिंदूर' की सफलता का भी जिक्र होगा। इससे यह स्पष्ट

संदेश दिया जाएगा कि भारतीय वायुसेना हवा में दबदबा बनाने और लंबी दूरी तक सटीक वार करने में पूरी तरह सक्षम है। 'वायुशक्ति 26' में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलिकॉप्टर अपनी समन्वित क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सटीक निशाना, तेज गति और तालमेल का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।

रेगिस्तान की धरती पर जब भारतीय वायुसेना के विमान आकाश में गर्जना करेंगे, तब पोखरण एक बार फिर देश की सैन्य ताकत और आत्मविश्वास का साक्षी बनेगा। 'वायुशक्ति 26' केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की सशक्त और सजग हवाई क्षमता का जीवंत संदेश है। 'वायुशक्ति' का जबरदस्त प्रदर्शन पाकिस्तान बॉर्डर के समीप राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण रेंज में हुआ।

एक खास बात यह भी है कि यह अभ्यास दिन, शाम और रात तीनों परिस्थितियों में संचालित होगा। अलग अलग मिशनों के जरिए वायुसेना चौबीसों घंटे की युद्ध तत्परता को दर्शाएगी। मुख्य आयोजन से पहले पोखरण फील्ड एंड फायरिंग रेंज में ही फुल ड्रेस रिहर्सल की गई।

दरअसल, भारतीय वायु सेना सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे प्रचंड जवाब देने वाली शक्ति के रूप में जानी जाती है। इस अभ्यास में दिखाया जाएगा कि अगर दुश्मन कोई हरकत करता है तो उसे किस तेजी और सटीकता से जवाब दिया जा सकता है। दिन हो, शाम हो या रात, हर परिस्थिति में ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता का प्रदर्शन होगा। वायुसेना के मुताबिक, अभ्यास में यह भी दिखाया जाएगा कि भारतीय वायुसेना केवल युद्धकाल में ही नहीं, बल्कि शांति और आपदा के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

देश और विदेश में संकटग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित एयरलिफ्ट, बचाव और निकासी अभियान चलाने की क्षमता का प्रदर्शन भी इस अभियान का हिस्सा होगा। यहां आधुनिक हथियारों जैसे आकाश मिसाइल, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन और एंटी-ड्रोन सिस्टम का भी प्रदर्शन किया जाएगा।'वायुशक्ति-26 के जरिए वायुसेना देश को यह भरोसा दिला रही है कि वह हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यहां वायुसेना दिखाएगी की उसका वार अचूक, अभेद्य और सटीक है।

‘बक्शी का तालाब’ के निकट हुआ थ

जब आप लखनऊ से सीतापुर की ओर चलेंगे तो बख्शी का तालाब पुलिस स्टेशन परिक्षेत्र जहां समाप्त होता है वहीं से यू टर्न लेकर वापस लखनऊ की ओर लौटें और दाहिनी ओर घूम जाइए। लगभग एक किलोमीटर चलेंगे तो आप को एक छोटा सा गांव देवरी रुखारा दिखाई देगा। गांव में घुसने के पहले लगभग 10 एकड़ जमीन में एक बरगद का पेड़ और प्राचीन काल का छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। जिसे मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है । कहते हैं कि यही वह जगह है जहां दानव बाणासुर और भगवान श्रीकृष्ण के बीच युद्ध हुआ था । वर्तमान में युद्ध के कोई साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं । लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कथा है । जिसके बारे में मंदिर के पुजारी नागा बाबा भैरव कुंज बताते हैं कि बाणासुर की खूबसूरत बेटी थी उषा । उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा । चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत ही माहिर थी।

एक बार उषा ने एक खूबसूरत युवक को देखा और उस पर मोहित हो गई। वह इस कदर मोहित हुई कि वह उसके बिना अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगी । कई दिनों से वह उसी के कल्पनाओं में जीती रही लेकिन वह युवक फिर नहीं दिखा। बताते हैं कि उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा को यह बात बताई और कहा कि वह चित्रकला बनाने में माहिर है इसलिए वह ऐसे सुंदर पुरुष का चित्र बनाएं जिसे देखकर वह जान जाएगी वह वही युवक था। चित्र लेखा ने सहेली की बात सुनकर बहुत सारे सुंदर युवकों के चित्र बनाएं । जिसमें से एक चित्र पर उषा ने अपनी उंगली रख कर कहा कि यह ठीक वहीं युवक है जिसे उसने देखा था। जिस चित्र पर उषा ने अपनी उंगली राखी थी, उसे देख कर चित्रलेखा के होश उड़ गए। उसने सहेली को बताया कि यह तो श्री कृष्ण का भांजा है । लेकिन उषा अपनी बात पर अड़ी रही। बात श्री कृष्ण तक पहुंची ,उन्होने ने बाणासुर को समझाया भी। कहते हैं कि बेटी की जिद्द के आगे बाणासुर झुकने को राज़ी नहीं हुआ । जिसके परिणाम स्वरूप इसी जगह पर श्री कृष्ण एवं बाणा सुर के बीच युद्ध हुआ, जिसमे बाणा सुर बुरी तरह पराजित भी हुआ। जिसके चलते श्री कृष्ण का भांजा उषा का भी न हो सका।

पुजारी के साथ लेखक

मंदिर के पुजारी नागा बाबा भैरव कुंज इस बात को नहीं बता पाते हैं कि यहां पर युद्ध हुआ था परंतु मंदिर का निर्माण कैसे और क्यों किया गया । स्थानीय लोगों के मुताबिक यह मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है जहां पर हजारों साल पुराना एक बरगद का विशाल वृक्ष आज भी विद्यमान है । जो

ा बाणासुर व श्री कृष्ण के बीच युद्ध

मुक्तेश्वर नाथ मंदिर

पूरी तरह सुख चुका है। लेकिन उसकी उप शाखाओं के चलते वह अभी भी जमीन पर खड़ा है । इस वृक्ष के बारे में एक किवदंती भी है। गांववालों के मुताबिक जिसकी पुष्टि बाबा भैरव कुंज भी करते हैं कि हर साल नाग पंचमी के दिन इस पेड़ से सफेद रंग के नाग- नागिन का दर्शन होता है। जिसे देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। इसी कारण यहाँ पर तीन दिनों तक नाग पंचमी का मेला भी लगता है। बाबा बताते हैं कि इस क्षेत्र में तरह-तरह की सांप , नाग, बिच्छू व अन्य जीव-जन्तु घूमते हुए दिखाई देते हैं । लेकिन इनसे कभी किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है ।

बाबा भैरों कुंज महाराज बताते हैं कि इस परिसर में पाँच शिव लिंग हुआ करते थे ,लेकिन आज यहाँ पर चार ही हैं। जो मुख्य मंदिर से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हैं। मुख्य मंदिर के भवन के पीछे वह कहते हैं कि पहले यह मंदिर जीर्णशीर्ण अवस्था में था। सन 1936 मैं राजा रामपाल ने इस मंदिर का निर्माण कराया। बाद में बाराबंकी के एक शिव भक्त ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया।

उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार वह यहाँ आए और बाबा भोले नाथ से संतान प्राप्ति की इच्छा जाहीर की । जब उनके आँगन में बच्चे की किलकारी गूंजी तो उन्होने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया । वे कहते हैं कि इस शिव मंदिर का संबंध मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित मंदिर से भी है। मंदिर परिसर में छोटे-छोटे और कई मंदिर भी हैं विशेष बात यह है कि यहाँ पर एक सेमर का प्राचीन पेड़ है, जिसके चारों ओर गणेश जी की आकृति आज भी बनी है। मंदिर को पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन तो ले रखा है लेकिन रखरखाव के नाम पर आज तक वहां पर कुछ नहीं हुआ। मंदिर में भगवान शिव का एक मुकुट है जिसे हर वर्ष शिवरात्रि के दिन भक्तों के दर्शनार्थ निकाला जाता है। जब भी आप सीतापुर से लखनऊ आएं या जाएं तो इस मंदिर का जरूर दर्शन करें।■

अयोध्या में अब हर श्रद्धालु को 'अतिथि देवो भव:' की भावना के अनुरुप मिलेगा सत्कार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन के तहत तेजी से संवर रही रामनगरी में आने वाले अब हर श्रद्धालु को 'अतिथि देवो भव:' की भावना के अनुरूप सत्कार मिलेगा। इसके लिए रामकथा पार्क में एक आधुनिक नवीन पर्यटक आवास गृह (गेस्ट हाउस) का निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहा है। यह परियोजना अयोध्या में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ठहरने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रामकथा पार्क पहले से ही रामायण की कथाओं को जीवंत रूप में दर्शाने वाला महत्वपूर्ण स्थल है, अब एक नए जी+3 मंजिला भवन के रूप में और आकर्षक बनने जा रहा है। इस पर्यटक आवास गृह में कुल 34 कमरों की सुविधा उपलब्ध होगी, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आरामदायक ठहरने का विकल्प प्रदान करेगी। भवन की कुल अनुमानित लागत 2421.08 लाख रुपये है। यह निर्माण कार्य यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई -11 अयोध्या की देखरेख में हो रहा है, जबकि पीपीई प्रणाली के तहत एलएंडटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। एलएंडटी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के हाथों में होने से निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया हुआ है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यहां पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ऐसे में ठहरने की सुविधाओं का विस्तार अनिवार्य हो गया था। रामकथा पार्क में यह नया आवास गृह न केवल सामान्य पर्यटकों के लिए बल्कि मध्यम वर्ग के श्रद्धालुओं के लिए भी किफायती और सुविधाजनक विकल्प साबित होगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहे अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे घाटों का सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, टेंट सिटी और थीम पार्क आदि के साथ यह नया पर्यटक आवास गृह अयोध्या की छवि को और निखार देगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा पर्यटक आवासइस नए पर्यटक आवास गृह को पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसमें 34 कमरें, किचिन, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, वातानुकूलित कमरे, रिसेप्शन लॉबी, आधुनिक स्नानघर, वाई-फाई, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। कमरों का डिजाइन ऐसा रखा गया है कि पर्यटक रामकथा पार्क की हरियाली और रामायण से जुड़े वातावरण का पूरा आनंद ले सकें। पार्क में रामायण के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाने वाली मूर्तियां, भित्ति चित्र और अन्य आकर्षण पहले से मौजूद हैं, और यह नया गेस्ट हाउस इन्हें और अधिक सुलभ बनाएगा।जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा प्रोजेक्टयूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड अयोध्या के परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जा सके और पर्यटकों को इसका लाभ मिल सके। रामकथा पार्क पहले से ही एक लोकप्रिय स्थल है, जहां लोग रामायण की कथाओं को सुनते और देखते हैं। अब इस नए गेस्ट हाउस के बनने से पार्क का महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि पर्यटक यहां ठहरकर आसानी से राम मंदिर, सरयू घाट और अन्य निकटवर्ती स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण से किसानों व युवाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के ठोस प्रयास

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र मे किसानो व उद्यमियो की आमदनी बढ़ाने तथा युवाओं के लिए रोजगार की अपार सम्भावनायें है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिये हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत दी जा रही सुविधाओं तथा प्रदत्त व प्राविधानित अनुदान आदि के बारे मे लोगो को जागरूक व प्रेरित किया जाय, ताकि अधिक से अधिक उद्यम स्थापित हो सकें।

इस दिशा मे खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानो के उत्पादो का अधिक से अधिक दाम दिलायें। विकसित भारत के निर्माण मे खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य के मार्गदर्शन मे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लगातार स्वीकृति मिल रही है और उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंद बन रहा है। खाद्य प्रसंस्करण से किसानो व युवाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 से उद्यमियों को नये आयाम मिल रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र मे रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं। नीति से स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा और गांव-गांव तक औद्योगिक समन्वय पहुंच रहा है। यूपी मे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री निवेश व रोजगार का नया केंद्र बन रही है।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा देश की सर्वात्तम उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनायें संचालित है। इस योजना में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, रेडी टू इट / रेडी टू कुक खाद्य पदार्थ/ब्रेक फास्ट सिरियल्स /स्नैक्स / बेकरी एवं अन्य खाद्य पदार्थ, अनाज

/ दाल एवं तिलहन प्रसंस्करण, अन्य कृषि / बागवानी उत्पाद-स्पाइस, सोयाबीन, मशरूम प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, कोको उत्पाद, गुड आधारित वैल्यू एडेड उत्पाद, फूट जूस / पल्पस तैयार कार्बानेटेड पेय पदार्थ, अन्य क्षेत्र के खाद्य उत्पादों जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, एवं मुर्गी / मछली चारा निर्माण इकाई जैसे सेक्टर्स आच्छादित है।

उप मुख्यमंत्री के निर्देशो के क्रम मे विभाग द्वारा बहुत ही प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। इसी कड़ी मे उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र० शासन, बी एल मीना की अध्यक्षता में रेशम निदेशालय गोमतीनगर लखनऊ अप्रैजल समिति की बैठक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में 16 प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसके सापेक्ष 15 प्रस्तावों को समिति द्वारा नीति अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार अर्ह पाया गया तथा एस०एल०ई०सी० के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अनुसंशा की गयी। इनमे लगभग रू0140 करोड़ के निवेश होगे।

अप्रेजल में जनपद कानपुर नगर का 02, कानपुर देहात का 01, हाथरस का 01, एटा का 01, शाहजहाँपुर का 01, शामली का 01, अमेठी का 02, प्रयागराज का 01, गोरखपुर का 01, जालौन का 01, कुशीनगर का 01, बाराबंकी का 01, बाराणसी का 01 एवं मुरादाबाद का 01 प्रोजेक्ट सम्मिलित किया गया, जिसमे 15 प्रोजेक्ट की मंजूरी अप्रेजल समिति द्वारा की गयी इन15 प्रोजेक्ट्स में से सोलर प्रोजेक्ट्स-06, डेयरी प्रोड्क्ट्स-01, रेडी टू कूक-01, रेडी टू ईट-01, कुक्कुट आहार-01, प्रोजेन फ्रूट एवं वेजिटेबल-01, लिक्विड ग्लूकोज-01, डी-आयल्ड -01, टोमैटो सास-01, एवं ट्रांस्पोर्ट सब्सिडी 01 प्रोजेक्ट को आगामी एस०एल०ई०सी० में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी। इसके अतिरिक्त मिल्क, चीज, बटर, पनीर, दही से संबन्धित सहारपुर के 01 प्रोजेक्ट को भी आगामी एस०एल०ई०सी० में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गये।

स्क्रीन से रखो उतनी ही करीबी जितनी हो बहुत जरूरी

डिजिटल डिटाक्स अपनाएँ यानि स्क्रीन से थोड़े समय की नियमित दूरी बनाएं

मुकेश शर्मा (एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर)
पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया

देश और दुनिया में बढ़ती तकनीक ने जहाँ एक ओर हमें सशक्त बनाने का काम किया है वहीँ अब एक ऐसा भी वक्त आ गया है कि डिजिटल उपकरणों (स्क्रीन) ने तो हमें पूरी तरह से अपने वश में ही कर लिया है। सुबह आँख खुलने के साथ ही हम सबसे पहले अपना मोबाइल तलाशते हैं। नाश्ता करते-करते टीवी की स्क्रीन पर निगाह रखते हैं। काम पर पहुंचकर कम्प्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के साथ ही स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी निगाह होती है। यदि गंभीरता से विचार करें तो यह जरूर एहसास होगा कि इस पूरे दौरान बहुत सा ऐसा वक्त था जब स्क्रीन पर बने रहना कोई बहुत जरूरी नहीं था। डिजिटल उपकरणों खासकर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लगातार बने रहने की यही गुलामी विभिन्न शारीरिक समस्याओं को जन्म दे रही है, इसलिए आज की जरूरत यही है कि स्क्रीन के करीब उतनी ही देर रहा जाए, जितनी देर रहना बहुत जरूरी हो। इंसान, इंसानियत, प्रकृति, भावुकता एवं सदव्यवहार आज के नितांत आवश्यक बिंदु हैं, जो हमारी जिन्दगी को ज्यादा खुशगवार व स्वस्थ बना सकते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि स्क्रीन से थोड़े समय की नियमित दूरी।

यदि आप भी नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं, ध्यान को केन्द्रित करने में दिक्कत आ रही है, शारीरिक रूप से असहज महसूस कर रहे हैं, समय का प्रबन्धन से ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, सामाजिक रूप से अपने को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। आज के दौर में कहा जाए तो आपको डिजिटल डिटाक्स (Digital Detox) अपनाने की जरूरत है यानि नियमित रूप से एक तय समय के लिए डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से जानबूझकर दूरी बनाने की सख्त जरूरत है। इसका कदापि यह मतलब नहीं है कि तकनीकी निर्भरता से दूर हो जाना बल्कि अनावश्यक स्क्रीन पर आँख गड़ाने से बचना है। अपनी दिनचर्या कुछ इस तरह से तय करने की जरूरत है कि हर रोज कम से कम एक घंटे का समय ऐसा जरूर हो जब हम अपने को मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। उस कीमती समय में प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिता सकते हैं, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम या अपनी खास रुचि का कुछ काम कर सकते हैं। समाचार पत्र, पुस्तक आदि पढ़ने की आदत विकसित कर सकते हैं।

इससे जहाँ मानसिक तनाव में कमी आएगी वहीँ अच्छी नींद भी आएगी। सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आने के साथ ही मानसिक एकाग्रता भी बढ़ेगी। मोबाइल पर आने वाले गैर जरूरी नोटिफिकेशन को साइलेंट रखना भी बेहतर हो सकता है। इसकी शुरुआत धीरे-धीरे की जा सकती है और एक घंटे की समय सीमा को अपनी सुविधा के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही एक तरीका यह भी अपनाया जा सकता है कि अपने वरिष्ठों और सहयोगियों को बातचीत के दौरान यह अवगत करा सकते हैं कि कार्यालय अवधि के बाद प्रतिदिन एक निर्धारित अवधि के दौरान मोबाइल या अन्य डिजिटल उपकरणों से दूर रहने के कारण ई मेल आदि का जवाब मिलने में विलम्ब हो सकता है। इसके लिए अपने साथियों को भी प्रेरित करें कि वह भी प्रतिदिन कुछ वक्त डिजिटल उपकरणों से दूर रहकर अपनों के साथ समय व्यतीत करें या कुछ खास रूचि के कामों में अपने को व्यस्त रखें। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही जीवन शैली को संतुलित करने का भी एक एक सशक्त माध्यम बन सकता है। चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि भोजन करते वक्त तो कम से कम स्मार्टफोन या टीवी को पूरी तरह बंद रखें और परिवार से बात करें। ऐसा करने से रिश्ते मजबूत बनते हैं और आपसी समझ बढ़ती है। इसके अलावा कोशिश करें कि घर का एक ऐसा कोना जरूर हो जो कि स्क्रीन फ्री जोन के रूप में हो, यह आपका बेडरूम या डाइनिंग एरिया भी हो सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन और लैपटॉप पर काम करते वक्त शरीर की सही मुद्रा का होना भी जरूरी है। स्क्रीन हमेशा आँखों के स्तर पर होनी चाहिए।

आज छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में भी स्मार्टफोन आसानी से देखा जा सकता है। इससे उनमें शुरू से यह आदत बनती जा रही है कि मोबाइल की स्क्रीन पर कार्टून देखते हुए ही खाना खाएंगे। एक वक्त था जब मां या परिवार के बड़े-बुजुर्ग बच्चों को लोरी या कोई प्रेरणादायक कहानी सुनाते हुए खाना खिलाते थे, जिससे बच्चे का एक जुड़ाव परिवार से बनता था और उसमें उत्सुकता भी रहती थी कि फिर क्या हुआ उससे उनकी तर्क शक्ति भी बढ़ती थी। आज के समय में संयुक्त परिवार का दायरा सीमित होने के साथ ही कामकाजी माता-पिता भी बच्चों को पर्याप्त समय चाहकर भी नहीं दे पाते। ऐसे में जरूरत है कि सोशल मीडिया या टीवी सीरियल से कुछ वक्त बचाकर बच्चे को जरूर दें, कुछ उनकी सुनें और कुछ अपनी कहें। किशोर वर्ग भी मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर पढ़ाई के साथ घंटों सोशल मीडिया पर समय व्यतीत कर रहा है, जिससे आँखों को नुकसान पहुँचने के साथ ही वह अपने को घर-परिवार से भी पूरी तरह से नहीं जोड़ पा रहा है।

(लेखक पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं)

बारहवाँ ज्योतिर्लिंग

'घृष्णेश्वर मंदिर'

विष्व प्रसिद्ध एलोरा (स्थानीय बोलचाल की भाषा में वेलूर) की गुफाओं समीप ही प्रसिद्ध बारहवाँ ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर मंदिर है। यह भगवान शिव के १२ ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव के ज्योर्तिलिंगों की सूची में ये १२वां और आखिरी है। यहां आकर एक विशेष प्रकार के शांत वातावरण का एहसास होता है। यह मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तंजौर स्थित वृहदेश्वर मंदिर (बिग टेंपल) का लघु रूप सा दिखाई है। कला शिल्प की दृष्टि से ये अति सुंदर मंदिर है।

इस मंदिर का जीर्णोद्धार सर्वप्रथम सोलहवीं शताब्दी में वेरुल के ही मालोजी राजे भोंसले (छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा) के द्वारा कराया गया। फिर अठारहवीं सदी में इस मंदिर को इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा भव्य रूप प्रदान किया गया।पता हो कि अहिल्याई बाई होल्कर ने सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया था। घूश्वमेश्वर मंदिर पूरी तरह पत्थरों का बना हुआ है। दीवारों पर सुंदर नक्कासी देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। लोकप्रिय एलोरा की गुफाओं के प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी महज आधा किलोमीटर है। शहर से दूर स्थित यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह १२वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घुसृणेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यहां सोमवार को भारी भीड़ होती है।

शिव महापुराण में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। ज्योतिर्लिंग 'घुश्मेश' के समीप ही एक सरोवर भी है. जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है।

देश में कहां-कहां हैं 12 ज्योतिर्लिंग

1. सोमनाथ (गुजरात)
2. श्री मल्लिकार्जुन स्वामी (करनूल, आंध्र प्रदेश)
3. महाकालेश्वर (उज्जैन, मध्य प्रदेश)
4. ओंकारेश्वर (खंडवा, मध्य प्रदेश)
5. केदारनाथ (रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड)
6. भीमाशंकर (मंचर, पुणे, महाराष्ट्र)
7. काशी विश्वनाथ (वाराणसी, उत्तर प्रदेश)
8. त्र्यंबकेश्वर (नासिक, महाराष्ट्र)
9. वैद्यनाथ (देवघर, झारखंड)
10. नागेश्वर (द्वारका, गुजरात)
11. रामेश्वरम (रामनाथपुरम, तमिलनाडु)
12. घृष्णेश्वर मंदिर (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

कहा जाता है कि जो भी इस सरोवर का दर्शन करता है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंदिर में दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है।

ईदृशं चैव लिंग च दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते।
सुखं संवर्धते पुंसां शुक्लपक्षे यथा शशी।।

अर्थात् घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं । मंदिर में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं। मंदिर का गर्भ गृह जहां शिवलिंग स्थित है वह सभा मंडप की तुलना में गहराई में है। गर्भगृह में जाने वाले पुरुषों को कमर के ऊपर का वस्त्र उतारना पड़ता है।

मंदिर के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है , जिसके मुताबिक देवगिरि पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषियों ने बताया कि सुदेहा को संतान नहीं हो सकती। सुदेहा ने सुधर्मा को दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करने को कहा। पत्नी की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। वह पत्नी की छोटी बहन घुश्मा से विवाह कर ले आए। घुश्मा भगवान शंकर की भक्त भी थी। रोज एक सौ एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। भगवान आशुतोष की कृपा से उसे एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र हुआ। पर ईष्या वश सुदेहा ने पुत्र को मार डाला मगर परम शिवभक्त सती धुश्मा के आराध्य शिव ने उसे पुनर्जीवित कर दिया और स्वयं घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए।

ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही जगदगुरु जनार्दन स्वामी मौनागिरी जी महाराज का समाधि मंदिर है। यह समाधि स्थल काफी साफ सुथरी है और यहां साधुओं का डेरा रहता है। आश्रम में आकर श्रद्धालु लोग परिक्रमा लगाते हैं।

(मोबाइल और कैमरा प्रतिबंधित - मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। मोबाइल फोन लेकर भी नहीं जा सकते। प्रवेश द्वारा पर मोबाइल फोन और कैमरा जमा करने का काउंटर बना हुआ है। इसके लिए मामूली किराया वसूला जाता है। मंदिर में श्रद्धालु दुग्धाभिषेक करते हैं। हमें सुबह सुबह स्थानीय लोग इसके लिए दूध बेचते नजर आते हैं।)■

'जन जन की सरकार, जन जन के द्वार' अभियान से आम जन को मिली रही राहत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास खंड परिसर चिन्यालीसौड़ में आयोजित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम में विभागीय स्टालों का निरीक्षण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्या एवं शिकायतें सुनते हुए मौके पर ही अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश समस्याओं का निस्तारण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम से आम जन को राहत मिली है तथा प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुगम और पारदर्शी हुई है। इस अभियान के तहत अब तक 600 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में पाँच लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जबकि 40 हजार से ज्यादा लोगों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य से अभियान चलाकर गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से आमजन को राहत मिली है और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुलभ एवं पारदर्शी बनी है।

सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में हैली सेवा के विस्तार के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिए है। उन्होंने कहा कि चिन्यालीसौड़ एवं गौचर हवाई पट्टी से हैली सेवा शुरू होगी। दोनों हवाई पट्टी सेना के माध्यम से संचालित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। सरकार ने यात्रा की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। ताकि यात्री, श्रद्धालु यहां से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यात्रा शुरू कराने में समन्वयक के रूप में है जबकि असली यात्रा

शुरू कराने में स्थानीय हितधारक, तीर्थ पुरोहित, होटल, टैक्सी, मैक्सी स्थानीय लोग है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में सनातन का उद्घोष हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर

> *राज्य सरकार द्वारा संचालित "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम से आम जन को राहत मिली है तथा प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुगम और पारदर्शी हुई है। इस अभियान के तहत अब तक 600 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।*

बनेगा प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसमें उत्तराखंड भी अपना महत्वपूर्ण रूप से योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि हमारी बहनों द्वारा उत्पादित उत्पादों की देश ही नही बल्कि दुनिया में पहचान मिल सके जिसके लिए निरंतर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा जो भी उत्पाद बनाये जा रहे है उसकी देश और दुनिया में मांग बढ़ी है। इस दिशा में राज्य सरकार ने अब तक दो लाख से अधिक लखपति दीदियों को सशक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की मांग पर सीएचसी चिन्यालीसौड़ एवं महाविद्यालय का उच्चीकरण को सीएम घोषणा में सम्मिलित करने का आश्वसन दिया। मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जन-जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया है। जिसमें अब तक 5 लाख से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया तथा 40 हजार से अधिक नागरिकों के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए गए। ग्रामीणों की छोटी-छोटी समस्याओं के निस्तारण के लिए संयुक्त टीमें गठित कर समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। जिनका निस्तारण नही किया जा सका उन्हें ऑनलाइन कर नियमित रूप से फॉलोअप करते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा।

पुरुष और महिला खिलाड़ियों के सालाना प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को 2025-26 सीजन के लिए भारतीय टीम के सीनियर पुरुष और सीनियर महिला खिलाड़ियों के सालाना प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड-बी में रखा गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी होगा।ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय क्रिकेट में एक स्पष्ट पीढ़ीगत बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें शुभमन गिल को जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के साथ सीनियर पुरुषों के लिए ग्रेड-ए में शामिल किया गया है। बुमराह टॉप ग्रेड में एकमात्र तेज गेंदबाज बने हुए हैं, जो सभी परिस्थितियों में उनके महत्व को दर्शाता है। रवींद्र जडेजा को ग्रेड-ए में बनाए रखना एक ऑलराउंडर के तौर पर उनके मूल्य को दर्शाता है।ग्रेड-सी लिस्ट सबसे बड़ी है, जिसमें उभरती प्रतिभाओं और फॉर्मेट विशेषज्ञों का मिश्रण है।

इसमें अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन जैसे युवाओं को भी लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद पुरस्कृत किया गया है। वहीं, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को ग्रेड-बी में स्थान मिला है।

टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) वार्षिक अनुबंध 2025-26:

ग्रेड-ए: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा।

ग्रेड-बी: वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जयसवाल, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर।

ग्रेड-सी: अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़।

दूसरी ओर, महिलाओं में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिगेज और दीप्ति शर्मा ग्रेड-ए लिस्ट में हैं। महिलाओं के कॉन्ट्रैक्ट में कई युवा नाम भी हैं।शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा, यास्तिका भाटिया और हरलीन देओल जैसी खिलाड़ी ग्रेड-बी और ग्रुप-सी में शामिल हैं, जबकि उमा छेत्री, क्रांति गौड़ और काश्वी गौतम जैसे नए चेहरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं।

टीम इंडिया (सीनियर महिला) वार्षिक अनुबंध 2025-26:

ग्रेड-ए: हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिगेज और दीप्ति शर्मा।

ग्रेड-बी: रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और स्नेह राणा।

ग्रेड-सी: राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतीका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, हरलीन देओल, काश्वी गौतम, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा और तेजल हसबनीस।

औषधीय गुणों का भण्डार नीम

नीम की पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं। यह शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती हैं, लिवर और हृदय को स्वस्थ्य रखती हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। बहुत से लोग नीम की पत्तियों को उसके कड़वे स्वाद की वजह से नहीं खाते।

जब हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी हो या फिर त्वचा से संबंधित किसी समस्या से छुटकारा पाना हो, हर मर्ज का इलाज करती है नीम। नीम फायदेमंद औषधि है। स्वाद में कड़वा नीम सेहत को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। नीम का पानी आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इस पानी में कई ऐसे पोषक तत्व जैसे एंटी-इंफ्लेमेटरी एंटी-फंगल, एंटी-बैक्टीरियल आदि होते हैं, जो कई रोगों से शरीर को बचाए रखती है। नीम का पानी पीने या नीम की पत्तियों को सुबह खाली पेट चबाने से भी सूजन, घाव, मुंहासों, पेट की समस्याएं, बालों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। नीम की पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं। यह शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती हैं, लिवर और हृदय को स्वस्थ्य रखती हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। बहुत से लोग नीम की पत्तियों को उसके कड़वे स्वाद की वजह से नहीं खाते। मगर आयुर्वेद के अनुसार रोज सुबह खाली पेट नीम का सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है साथ ही शारीरिक विकारों को दूर करने में भी मदद मिलती है।

इम्यूनिटी बढ़ाएं कोरोना काल में स्वस्थ और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना है, तो नीम की पत्तियों

का सेवन करें। नीम का काढ़ा या फिर इसका पानी पिएं। नीम में एंटी-इंफ्लेमेटरी एंटी-फंगल, एंटी-बैक्टीरियल पोषक तत्व होते हैं, जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यदि आप गंभीर रोगों से बचे रहना चाहते हैं, तो आज से ही पीना शुरू कर दें नीम का पानी।नीम की पत्तियों का सेवन करने से शरीर कई बीमारियों से बचा रह सकता है। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आज ही घर पर नीम की चटनी बनाएं।रोज सुबह खाली पेट खाएं नीम की चटनी, वायरस और इंफेक्शन की कर देगी छुट्टी।

पेट में दर्द रहता है, कीड़े हो गए हैं, आंतों में सूजन है, तो भी नीम का पानी पीना फायदेमंद है। नीम चबाने या इसके पानी को पीने से गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्रैक्ट में हुए सूजन की समस्या में भी आराम मिलता है। पेट के अल्सर को कम करता है। पेट का फूलना, पेट में दर्द, ऐंठन, कब्ज आदि दूर करता है। पेट के फ्लू और संक्रमण से परेशान हैं, तो नीम का सेवन जरूर करें। यह एक ही दिन के अंदर पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है।

त्वचा और बालों के लिए भी नीम का पानी बेहद ही फायदेमंद है मुंहासे, फोड़े-फुसियां, स्किन एलर्जी, खुजली, एक्जिमा, स्किन रैशेज, दाग-धब्बों जैसी समस्याएं अक्सर बारिश या गर्मी के मौसम में अधिक नजर आती हैं। नीम का पानी पिएंगे, तो स्किन की समस्याओं से भी निजात मिलेगा। नीम के पानी में विटामिन ई, एस्ट्रिंजेंट गुण होते हैं, जो त्वचा और बालों की देखभाल करते हैं। इसका एंटी-बैक्टीरियल गुण स्किन बैक्टीरिया को मारता है। सिर की खुलजी को दूर करता है।

कान में दर्द रहता है तो नीम का तेल इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद रहेगा, कई लोगों में कान बहने की भी बीमारी होती है, ऐसे लोगों के लिए भी नीम का तेल एक कारगर उपाय है।

अगर आप खाना बनाते वक्त या किसी दूसरे कारण से अपना हाथ जला बैठी हैं तो तुरंत उस जगह पर नीम की पत्तियों को पीसकर लगा लें, इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण घाव को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है।

दांतों के लिए कुछ वक्त पहले नीम की दातुन, ब्रश की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय थी। एक ओर जहां दांतों और मसूड़ों की देखभाल के लिए हम तरह-तरह के महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वहीं नीम की दातुन अपने आप में पर्याप्त होती है। नीम की दातुन पायरिया की रोकथाम में भी कारगर होती है। नीम के अर्क में डायबीटीज, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने, जड़, छाल और कच्चे फलों में शक्ति-वर्धक और मियादी रोगों से लड़ने का गुण भी पाया जाता है। नीम प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट से तो भरपूर है ही साथ ही इसमें जड़ीबूटी के गुण भी हैं। नीम शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती हैं, जिससे हमारा ब्लड सकुर्लेशन भी ठीक बना रहता है। बालों के लिए भी है फायदेमंद नीम एक बहुत अच्छा कंडीशनर है। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उसके पानी से बाल धोने से रूसी और फंगस जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। फोड़े और दूसरे जख्मों पर लगाने के लिए नीम काफी फायदेमंद होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि खून साफ न होने की वजह से समय-समय पर फोड़े हो जाते हैं, ऐसे में नीम की पत्ती को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाने से फायदा होता है। साथ ही इसके पानी से चेहरा साफ करने पर मुंहासे नहीं होते हैं।

नीम का पानी पीने से ओरल हाइजीन दुरुस्त होती है। इससे दांतों और मसूड़ों संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। इसमें चूंकि एंटी-बैक्टीरियल तत्व होते हैं, ये दांतों में मौजूद बैक्टीरिया का सफाया करते हैं। बैक्टीरिया मरने से सांसों और मुंह से बदबू आने की समस्या दूर हो जाती है। दांतों की कैविटी, सड़न, दर्द, दांतों के पीलेपन आदि समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है।

> ***त्वचा और बालों के लिए भी नीम का पानी बेहद ही फायदेमंद है मुंहासे, फोड़े-फुसियां, स्किन एलर्जी, खुजली, एक्जिमा, स्किन रैशेज, दाग-धब्बों जैसी समस्याएं अक्सर बारिश या गर्मी के मौसम में अधिक नजर आती हैं।***

बीएफटीए फिल्म अवार्ड्स 2026

फिल्म 'बूंग' ने सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म का जीता पुरस्कार

लक्ष्मीप्रिया देवी की फिल्म 'बूंग' ने बीएफटीए फिल्म अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्म निर्माता लक्ष्मीप्रिया देवी और 'बूंग' की पूरी टीम को बीएएफटीए फिल्म अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है।यह बड़ी कामयाबी भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल है और भारत की विविधतापूर्ण और सार्थक कहानी कहने की परंपराओं के लिए दुनिया भर में बढ़ती सराहना को दिखाता है।

फिल्म के सफर को भारत के फिल्म विकास और महोत्सव इकोसिस्टम ने समर्थन दिया है।आपको बता दें, बूंग को 2023 में वर्क इन

प्रोग्रेस लैब और फिल्म बाजार रिकमेंड्स के तहत फिल्म बाजार में बनाया गया था। ये पहल होनहार फिल्म निर्माताओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक उद्योग से जुड़ाव को मुमकिन बनाने के लिए की गई हैं।

इसके बाद फिल्म को 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया, जहां इसे सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर कैटेगरी में चुना गया, जिससे इसकी समालोचक प्रशंसा और पक्की हो गई।भारत सरकार और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म बाजार और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जैसे प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं, जो फिल्म निर्माताओं को मजबूत बनाते हैं, रचनात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं। इससे भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं तक पहुंचने के रास्ते बनाते हैं।■

General DIAGNOSTICS

GD Wellness Lucknow Special

(71 Parameters)

- CBC-Complete Hemogram Test(28)
- Hba1c (Whole Blood)
- Iron Studies (4)
- TFT with UTSH
- LFT (Liver Function Test) (11)
- Lipid Profile (8)
- Max Kidney Profile (10)
- Vitamin B12
- 25 OH Vitamin D
- hs- CRP
- Testosterone

MRP. ~~3800~~/- 2499/-

TRUSTED ACROSS THE WORLD

QUALITY ACCREDITED BY THE BEST INSTITUTIONS

TO AVAIL SERVICE

DOCTOR YESNO™

Call : 8765295384

OUR LABS

Navi Mumbai (2) | Maharashtra (2) | Delhi (2) | Bihar | Uttar Pradesh (2) | West Bengal | Jharkhand | Odisha | Chhattisgarh | Agartala | Madhya Pradesh

अखिल मसाले

शुद्ध, प्राकृतिक, एवं स्वादिष्ट

सेहत और स्वाद

अब आपके हाथों में

EXPORT 100% QUALITY

Email : enquiry@akhilmasale.com
Contact : 9984616905, 9415206293

www.akhilmasale.com
Customer care : 7275320036